fo"k; lwph | lEikndh; | कमल संदेश

लिब्रहान रिपोर्ट लीक

समाचार.................................. 5

संसद में आडवाणीजी........... 5

लेख

आयोग मतलब राजनीति
—रामबहादुर राय.......... 7

सरकार संरक्षित गुण्डाराज
—हृदयनारायण दीक्षित.... 23

मूल्यों की दोषपूर्ण नीति
—डा. भरत झुनझुनवाला.. 24

झारखण्ड विधानसभा चुनाव

घोषणापत्र के प्रमुख अंश....... 8

रिपोर्ट...................................... 13

राष्ट्रपति को पत्र.................... 16

अन्य

मातृशक्ति सम्मेलन.................. 22

संविधान सम्मान समारोह....... 29

प्रदेशों से

दिल्ली...................................... 18

मध्य प्रदेश.............................. 19

उत्तर प्रदेश.............................. 28

उत्तराखंड................................ 30

सम्पादक

çHkkr >k] lkIn

सम्पादक मंडल

lR;iky

d- d- 'kek

lathO dqekj flUgk

पृष्ठ संयोजन

/keZUæ dkS'ky

सम्पर्क

Mk- eqdthZ Lefr U;kl

ih-ih-&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ

ubZ fnYyh&110003

Qksu u- +91¼11½&23381428

QSDl ¼ +91¼11½&23387887

lnL;rk gsrq ¼ +91¼11½&23005700

सदस्यता शुल्क

okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

अपने साथ जो बुराई करे, उसके साथ भी भलाई करना चाहिए।
-नीतिशतक

कोड़ा का महाघोटाला, कांग्रेस भी हमप्याला

हर चेहरे से नकाब उतरना चाहिए

>k रखंड में विधानसभा 2009 के चुनाव पांच चरणों में हो रहे हैं। सन् 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अभी सन् 2009 के लोकसभा निर्वाचन में भी भाजपा चौदह लोकसभा में से आठ पर स्वयं और एक भाजपा समर्थित निर्दलीय जीती। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि झारखंड की जनता का नैसर्गिक विकल्प भाजपा है। आज यह बात जनता भी कह रही है और विरोधी भी समझ रहे हैं। अब भाजपा को रात–दिन मेहनत कर जनता की भावना को मत–पेटियों तक ले जाने के प्रयत्न में जुट जाना चाहिए।

'झारखंड' की पौने तीन करोड़ जनता में दो बातों की चर्चा व्यापक स्तर पर है। एक तो यह कि क्या मधुकोड़ा ने बतौर मुख्यमंत्री साढ़े चार हजार करोड़ रूपये स्वयं खाया होगा? अगर खाया है तो क्या अकेले खाया होगा? फिर सवाल उठता है कि जब अकेले नहीं तो साथ में कौन–कौन थे? पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा

➡

वंदेमातरम् जब राष्ट्रगीत है तब विरोधियों पर देशद्रोह का मुकद्दमा क्यों नहीं?

भारत का राष्ट्रगीत वंदेमातरम् है या नहीं। अगर है तो फिर इसे विवादास्पद बनाने की साजिश क्यों होती है? राष्ट्रगीत के विरूद्ध आवाज उठाने और इसे नहीं गाने का प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत कोई संगठन कैसे करता है? क्या राष्ट्रगीत, जो संसद के अवसान पर दोनों सदनों में गाया जाता है, उसका अपमान करने का अधिकार हमें भारत में किसी को देना चाहिए? अगर नहीं तो फिर क्यों दिया जाता है, उन संगठनों को, जो सरेआम वंदेमातरम् का मखौल उड़ाते हैं। भारत सरकार को वंदेमातरम् के मसले पर अब दो टूक निर्णय लेना चाहिए। केन्द्र सरकार का यह ढुलमुल रवैया स्वयं इस बात को दर्शाता है कि 'राष्ट्रगीत वंदेमातरम्' के प्रति केन्द्र सरकार के मन भी संशय है। यदि ऐसा है तो फिर क्यों नहीं केन्द्र सरकार यह घोषित करती है कि 'वंदेमातरम्' का अपमान इसे बर्दाश्त है। रोज–रोज के अपमान से तो अच्छा है, एक बार केन्द्र सरकार यह तय करके देखे तो सही कि वंदेमातरम् राष्ट्रगीत नहीं है। फिर केन्द्र सरकार को और इसका विरोध करने वालों को तत्काल पता लग जाएगा कि 'वंदेमातरम्' राष्ट्रगीत का विरोध करने का क्या हश्र होता है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रगीत का अपमान और उसके विरुद्ध साजिश करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई ही नहीं देशद्रोह का मुकद्दमा चलाए, जिससे भविष्य में राष्ट्रगीत के विरूद्ध किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो।

की यह बात कि मुझे यदि अधिक परेशान किया तो मैं सब की पोल खोल दूंगा, ने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया है। भारतीय राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति जनास्था वैसे ही हिल चुकी है। नेताओं के बारे में असहनीय बातें सुनने को मिलती है। नेताओं के बारे में आम जनप्रतिक्रिया यही रहती है कि ये देश को लुटने–खसोटने के लिए राजनीति में आते हैं।

यहां सवाल उठता है कि ये बेचारी जनता क्या करे? जब वह सुनती है कि एक मुख्यमंत्री मात्र 23 माह में साढे चार हजार करोड़ का लेन–देन कर सकता है तो शेष वे मुख्यमंत्री, जो वर्षों से पदभार संभाले रहे हैं, वे क्या–क्या करते होंगे? समय रहते पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा और इस घोटाले में शामिल सभी लोगों के विरूद्ध यदि मुकद्दमा कायम नहीं किया गया और मधुकोड़ा के डायरी या जो भी साक्ष्य मिलते हैं, उनका खुलासा नहीं किया गया तो देश को कैसे विश्वास होगा कि केन्द्र सरकार इतने बड़े घोटाले की जांच के प्रति ईमानदार है।

आज देश जानना चाहता है कि कोड़ा की डायरी में किनके नाम हैं। 'मधुकोड़ा घोटाला कांड' भारत की प्रशासनिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं के लिए चुनौती है। कितना बड़ा मजाक है कि साढ़े चार हजार करोड़ का घोटाला होता रहा और 23 माह में न तो प्रशासनिक आपत्ति आई और न ही राजनैतिक। हमारी व्यवस्था की चौपट स्थिति का इससे ताजा उदाहरण और क्या हो सकता है? अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रहित, राजनैतिक हित और जनताहित की दृष्टि से मधुकोड़ा महाघोटाला से जुड़े हर विचारणीय प्रश्न का हल ढूंढना ही चाहिए, अन्यथा राजनीति और प्रशासन के प्रति आम नागरिक में व्याप्त अनास्था कम होने के बजाए और बढ़ेगी। जब जनास्था शिखर पर होगी तो हम जानते हैं कि जनता सड़कों पर आती है और कानून को अपने हाथ में लेती है।

भगवान के लिए ऐसा न हो उसके पूर्व केन्द्र सरकार को चाहिए कि जल्द इस महाघोटाला की जांच समय सीमा पर कर जनता के सामने सच्चाई रख दे। ■

भाजपा अध्यक्ष का प्रधानमंत्री को पत्र

आस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों के हित में प्रधानमंत्री सक्रिय भूमिका निभाएं : राजनाथ सिंह

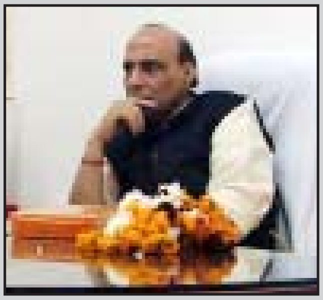

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने आस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों के खिलाफ चल रही हिंसा और भेदभाव विषय पर आस्ट्रेलिया की फेडरेशन के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को 12 नवम्बर 2009 को एक पत्र लिख कर उनकी सुरक्षा और हितों के प्रति सक्रिय उपाए करने का अनुरोध किया। पत्र की मूल प्रति का हिन्दी भावानुवाद नीचे प्रस्तुत है।

"आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

फेडरेशन आफ इण्डियन स्टूडेण्ट्स आफ आस्ट्रेलिया के संस्थापक श्री गौतम गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मेरे निवास पर आकर आस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक मुद्दों के बारे में मुझे जानकारी प्रदान की है।

इस संगठन ने मुझे बताया है कि पिछले एक–दो वर्षों में ही अकेले विक्टोरिया राज्य में 1447 मामले भारतीयों के विरूद्ध दर्ज किए गए हैं। इस संगठन का दावा है कि अधिकांश मामलों में पुलिस ने भारतीयों को मिथ्या ढंग से फंसाया गया है।

ये सदस्यगण उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार आस्ट्रेलिया में रह रहे सभी भारतीयों की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा करे और ठोस उपाए करे।

मेरा मानना है कि संगठन द्वारा अभिव्यक्त चिंता बहुत जायज है और इस पर प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की आवश्यकता है। इन दिनों आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री केविन रूड भारत की सरकारी यात्रा पर आ रहे हैं और सरकार उनसे विभिन्न प्रकार के व्यापक मुद्दों पर चर्चा करने वाली है। अतः, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के बातचीत के दौरान भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा और हितों के मुद्दे को उठाए और उनसे कहे कि भारतीय मूल के लोगों के साथ किए जा रहे भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए वे सुरक्षा उपाए करे।

मैं आस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर जिस ढंग से प्रगति चल रही है, उस पर भी मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। भाजपा का मानना है कि हमें आस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौता करते हुए भारतीय व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बराबरी का दर्जा बनाए रखना चाहिए और उनके कल्याण और श्रम–हितों को इस समझौते का अंतरंग अंग बनाना चाहिए।

सादर

jktukFk flag

अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बनाना मेरे जीवन की साध है : लालकृष्ण आडवाणी

लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट लीक होने के मुद्दे पर 23 नवंबर, 2009 को संसद में भारतीय जनता पार्टी, वामदल और सरकार को बाहर से समर्थन देर रहे सपा और बसपा ने इसे संसद की अवमानना करार देते हुए इसे सदन में तुरंत पेश करने की जोरदार मांग की और जबरदस्त विरोध किया। दोनों ही सदनों में भाजपा और शिवसेना के सदस्य अध्यक्ष एवं सभापति के आसन के समक्ष आकर नारे लगाने लगे। भाजपा सदस्य ''रिपोर्ट को पेश करो, झूठ बोलना बंद करो'' के नारे लगा रहे थे। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका और इनकी बैठक दो बार के स्थगन के बाद भोजनावकाश के पश्चात पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी।

एक अंग्रेजी दैनिक में रिपोर्ट के अंश लीक हो जाने से आक्रोशित लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने इसे सदन के विशेषाधिकार हनन का मामला बताया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर नियोजित तरीके से मीडिया में रिपोर्ट लीक की गयी। अखबार की खबर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आने पर हैरानी जाहिर करते हुए आडवाणी ने कहा, ''यदि मुझे दोषारोपित किया गया होता तो मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया होता। चिदंबरम ने स्पष्ट किया कि इस रिपोर्ट की मात्र एक प्रति गृहमंत्रालय के पास है और वह भी सुरक्षित स्थान पर है। लिहाजा इसके लीक होने का सवाल ही नहीं है।

लोकसभा में श्री आडवाणी ने लिब्रहान आयोग के समक्ष दी गयी अपनी गवाही का जिक्र करते हुए कहा कि मस्जिद गिराये जाना उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। लेकिन उन्होंने कहा कि अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहने पर व्यक्तिगत रूप से उन्हें गर्व है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, यह उनके जीवन की साध है। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि वहां जल्द भव्य राम मंदिर बने। लोकसभा में विपक्ष की उपनेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा कि गन्ना मूल्य के सवाल पर विपक्ष की जो एकजुटता बनी थी, वह सरकार को रास नहीं आ रही है और उसने असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए यह रिपोर्ट लीक करायी है। उन्होंने रिपोर्ट को तत्काल सदन में पेश किए जाने की मांग की। राज्यसभा में गृह मंत्री के बयान के बाद विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने इसे बेहद गंभीर मामला करार देते हुए कहा कि यह संसद के विशेषाधिकार से जुड़ा मामला है और सभापति को इस मुद्दे की जांच करनी चाहिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व सांसद श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि न्यायमूर्ति लिब्रहान भी आधिकारिक तौर पर यह कह चुके हैं कि आयोग की तरफ से रिपोर्ट लीक नहीं की गयी। नायडू ने अनुवाद तथा अन्य कारणों से रिपोर्ट को संसद में पेश किए जाने में हो रही देरी के सरकार के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट करीब छह महीने पहले ही सौंप दी गई थी और सरकार क्या इतने समय में इसका अनुवाद या एटीआर तैयार नहीं करवा पाई।

हम यहां लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा दिए गए भाषण का संपादित पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं :

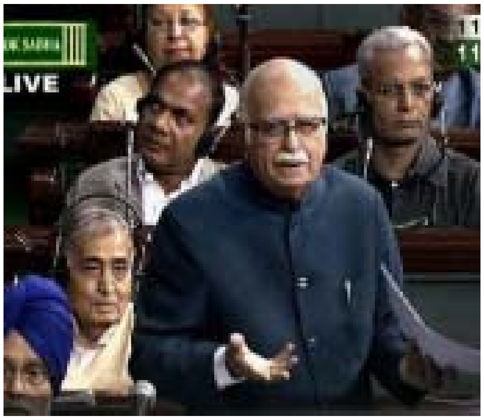

eझे जहां तक स्मरण आता है, मैंने जीवन में कभी पहले प्रश्नोत्तरकाल स्थगित करने की प्रक्रिया का उपयोग करने की कोशिश नहीं की। पहली बार मैंने नोटिस दिया है। आज प्रातः काल जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस देखा तो मैं हैरान हुआ कि अभी तक तो यह रिपोर्ट सदन के सामने भी नहीं रखी गयी, सदन को भी नहीं बतायी गयी, तो इंडियन एक्सप्रेस को किसने बतायी और क्यों बतायी? मेरे एक साथी ने ''इंडियन एक्सप्रेस'' के एडीटर से सीधे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कह सकता हूं कि यह ऑथेन्टिक है। इसमें कोई तथ्य हमने कपोल–कल्पित करके छापा हो, ऐसा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं। मैं आश्चर्यचकित हूं। अगर कोई यह कहता है कि आडवाणी अयोध्या के उस अवसर पर, लोगों को संग्रहित करके

वहां पर लाये, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां आए, इसीलिए यह घटना हो गयी। कोई कह सकता था, मैं अपेक्षा करता था कि शायद कोई कहेगा। इसमें इन्डाइटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें दो बातें कही गयी हैं।

सम्मानित सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि वह कतरन देकर ही उसके आधार पर मैंने प्रॉपर परमीशन मांगी है, क्योंकि I was shocked to see this report. जिस रिपोर्ट में मेरे वरिष्ठ नेता और काफी समय से अस्वस्थ चल रहे वाजपेयी जी को भी इनडाइट करने की बात कही गई है।

मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में मेरा अयोध्या मूवमैंट के साथ जुड़ना और वहां पर जनता की इच्छा के अनुसार उस स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बने, यह मेरे जीवन की साध है और जब तक यह साध पूरी नहीं होगी, मैं इसके लिए कार्य करता रहूंगा।

मुझे इनडाइट करते तो मैंने कहा कि मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करता, चुनौती मानता। हवाला में मुझे इनडाइट करने की कोशिश की, मैंने चुनौती मानी।

मेरा इनडाइटमैंट होता, मेरी पार्टी का इनडाइटमैंट होता, समझ में आता है, लेकिन वाजपेयी जी का उल्लेख देखकर मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य बन जाता है कि जिनके नेतृत्व में मैंने जीवनभर राजनीति में काम किया, उनके खिलाफ, उनकी आज की अवस्था में कोई इस प्रकार की बात कहे और कही गई है।

मैं इसलिए उसके बारे में डिटेल में नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि यह रिपोर्ट सरकार को जून के महीने में दी गई और जून के बाद आज नवम्बर का महीना पूरा होने को आया है, बीच में एक सैशन हो चुका है, उस समय गृह मंत्री जी ने यह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं रखी।

आज दूसरा सैशन शुरू हुए भी दो–तीन दिन हो गए हैं। हममें से बहुत सारे लोग समझते थे कि शायद पहले ही दिन यह रिपोर्ट रखी जाएगी, लेकिन नहीं रखी गई, दूसरे दिन नहीं रखी गई। आज तीसरा दिन है तो अचानक हम अखबार में मोटे तौर पर इस प्रकार की खबर देखते हैं और एडीटर कहते हैं कि यह ऑथैंटिक रिपोर्ट है। उसमें थोड़े–बहुत शब्द बदले होंगे, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद एक दिन का भी विलंब करने का अधिकार सरकार को नहीं है, तुरंत रखनी चाहिए।

मैं मांग करता हूं कि यह रिपोर्ट ज्यों की त्यों आज ही, सदन इसके बाद कोई दूसरी कार्यवाही न करे, इस रिपोर्ट को यहां पर रखने की मुझे इजाजत चाहिए। मैं दूसरी कोई मांग नहीं कर रहा हूं, मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर यह बात सही है जो इसमें लिखी है, तो यह दोनों बातें सरासर असत्य हैं, मैटिकुलसली प्लैंड। कोई षडयंत्र नहीं था, कोई योजना नहीं थी, यह घटना हुई जिस घटना के बारे में स्वयं लिब्रहान कमीशन के सामने कहा।

मैंने उसके बाद तुरंत लिखा हुआ है कि मेरे लिए एक बहुत दुखद दिन था, "It is the saddest day of my life." यह मैंने स्वयं लिब्रहान कमीशन के सामने कहा। उसकी एवीडैंस में भी आएगा। जहां तक मैंने देखा है कि इस रिपोर्ट में भी उसका थोड़ा सा उल्लेख है। लेकिन मोटे तौर पर मेरी मांग है कि आज बिना दूसरी कार्यवाही किए हुए गृह मंत्री जी इस सदन में वचन दें कि मैं तुरंत इस रिपोर्ट को लाकर सदन के सामने रखूंगा।...

इस रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है "to be continued?. इस रिपोर्ट को उन्होंने इतना ऑथैंटिक माना कि वे इसे सीरियली देने को तैयार हैं, एक–एक हिस्सा करके, धारावाहिक करके देने को तैयार हैं।

इस प्रकार की रिपोर्ट इस प्रकार अखबारों में छपती रहे, लीकेज होती रहे, It is a breach of privilege of the

शेष पृष्ठ 25 पर ...

भाजपा ने चिदंबरम पर रिपोर्ट 'लीक' करने का आरोप लगाया

भारतीय जनता पार्टी ने लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों को विकृत, निराधार व प्रस्तुत साक्ष्यों के खिलाफ बताया और कहा है कि इसका अध्ययन करने के बाद ही पार्टी विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया जताएगी। पार्टी ने गृह मंत्री पी. चिदंबरम पर रिपोर्ट लीक करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए।

लोकसभा में भाजपा की उपनेता सुषमा स्वराज ने संवाददाताओं से कहा कि यह रिपोर्ट प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की भी धज्जियां उड़ाने वाली है। रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी को दोषियों की सूची में रखा गया है। जब कि खुद आयोग ने उन्हें असलम भूरे की याचिका दायर किए जाने के बावजूद नहीं बुलाया था। यह याचिका भी खारिज कर दी थी। अगर उन्हें वाजपेयी पर संदेह था तो उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए था। इस रिपोर्ट की तमाम बातों को निराधार करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन करने के बाद पार्टी तर्कों व तथ्यों समेत अपना पक्ष संसद में रखेगी।

सुषमा स्वराज ने कहा कि अखबारों में इस रिपोर्ट के बारे में जो कुछ छपा वह अक्षरशः सही साबित हुआ। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि रिपोर्ट गृह मंत्रालय ने नहीं बल्कि गृह मंत्री ने लीक की है। उन्हें इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना था कि यह रिपोर्ट जस्टिस लिब्रहान ने भी लीक नहीं की है। उनका आरोप था कि सरकार रिपोर्ट पर चर्चा करने से बचना चाहती थी।

सुषमा स्वराज ने हालांकि जस्टिस लिब्रहान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सबसे हास्यास्पद बात यह है कि अपनी रिपोर्ट में उन्होंने अदालतों से इससे संबंधित मामलों की सुनवाई जल्दी पूरी करने को कहा है। वे यह भूल गए कि खुद उन्होंने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी। सुनवाई पूरी करने के पांच साल बाद अपना फैसला सुनाया।

आयोग मतलब राजनीति

jkecgknqj jk;

ft स मौके पर लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट लीक हुई है, उससे साफ पता चलता है कि यह आयोग राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बना था। इसके पीछे दूसरे मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश भी हो सकती है और झारखंड में चुनाव भी इसका कारण हो सकता है। 16 दिसम्बर 1992 को लिब्रहान आयोग बना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंहराव के एक सलाहकार हुआ करते थे ए.एन. वर्मा। बताया जाता है, वर्मा के यहां जस्टिस एम.एस. लिब्रहान किसी पद की लालसा में जाया करते थे।

वर्मा को लगा कि यह आदमी जैसा हम चाहेंगे, वैसा करेगा, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह देकर लिब्रहान को बाबरी विध्वंस की जांच के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष बनवा दिया। जब आयोग बना था, तब यह स्पष्ट रूप से लिखित था कि आयोग अधिकतम एक साल में अपनी रिपोर्ट दे देगा, लेकिन आयोग समय काटता रहा। छह–छह महीने कार्यकाल बढ़ता रहा। कुल 48 बार कार्यकाल बढ़ा। आयोग को इस बात का पता लगाना था कि 6 दिसम्बर 1992 की घटना स्वतःस्फूर्त थी या उसके पीछे षड्यंत्र था, यह खोजने में लिब्रहान को 17 साल लग गए। एक साल का काम 17 साल में किया गया। बीच में केन्द्र में पांच सरकारें बनीं और गईं। लिब्रहान की अध्यक्षता में जिस तरह से काम हुआ, उससे आयोग की निरर्थकता स्वयं साबित हो जाती है। आयोग की धीरे–धीरे विश्वसनीयता खत्म हो गई।

जांच आयोग एक कानून के तहत काम करता है। आयोग को सुबूतों के आधार पर केवल सिफारिश करनी होती है। उसके बाद सम्बन्धित मंत्रालय विचार करता है, अफसर रिपोर्ट पढ़ते हैं। उसके बाद वे कार्रवाई के लिए मंत्री से सिफारिश करते हैं। मंत्री उसे मंत्रिमंडल में ले जाते हैं, एटीआर अर्थात् एक्शन टेकेन रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्ट में कोई सनसनीखेज सिफारिश होने पर देखा जाता है कि उसकी पुष्टि के लिए ठोस सुबूत हैं या नहीं। उसके बाद अपराध दर्ज किया जाता है, गिरफ्तारी होती है।

जरूरी है कि लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संसद में पेश की जाए। सरकार को ऐसा करना ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आयोग राजनीतिक दावपेंच का हिस्सा था। रिपोर्ट 2009 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार पहले रिपोर्ट को उछालने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे आशंका थी कि रिपोर्ट आने से भाजपा के वोट बढ़ जाएंगे और यूपीए फिर सरकार नहीं बना पाएगी।

अब संसद चल रही है, सबसे बड़ा सवाल है कि किसने लीक किया। विपक्ष अगर दम दिखाए, तो सरकार को सकारात्मक रूप से घेर सकता है। वह मांग कर सकता है कि जिसने रिपोर्ट लीक की है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बहस का मुद्दा यह नहीं है कि लिब्रहान आयोग ने क्या सिफारिश की है, बहस तो इस पर होनी चाहिए कि उसने समय पर काम क्यों नहीं किया। आयोग के लिए आम लोगों की जेब अर्थात् सरकारी खजाने से जो पैसा खर्च हुआ है, वह लिब्रहान से क्यों न वसूला जाए? क्या ऐसे आयोगों का तमाशा संसद यों ही देखती रहेगी? क्या यही तरीका है, रिटायर्ड जजों को आयोगों का अध्यक्ष बना दिया जाए और वे कार्यकाल मनमर्जी से लगातार बढ़ते चले जाएं। इस बात पर विचार होना चाहिए कि निर्धारित समय में काम न करने वाले आयोग को बीच में ही क्यों न भंग कर दिया जाए। उससे जुर्माना क्यों न वसूला जाए?

ज्यादातर आयोगों का कार्य हास्यास्पद रहा है। जैन आयोग राजीव गांधी हत्या की षड्यंत्र की छानबीन के लिए बना था। आयोग ने आठ प्रारूप गढ़े थे, हरेक प्रारूप दूसरे प्रारूप को काटता था, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना दूर की कौड़ी थी। जैन आयोग ने 13 खंडों में रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को संसद की लाइब्रेरी में रख दिया गया, उसे कोई नहीं पढ़ता है, उसका कोई महत्व नहीं है। लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट का भी यही हश्र होने वाला है।

रिपोर्ट में क्या है, यह तो साफ तौर पर तभी पता चलेगा, जब रिपोर्ट संसद पटल पर आएगी। अभी कयास लगाए जा रहे हैं, रिपोर्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राव का नाम गायब है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर अखबार विशेष को रिपोर्ट दे दी गई। उस अखबार को समझ–बूझकर चुना गया है, ताकि सरकार की नाक न कटे। कई बार यह साबित हुआ है, यह बेपेंदी की सरकार है, कामकाज की निर्धारित परम्पराओं से इसका कोई लेना–देना नहीं है। लेना–देना होता, तो रिपोर्ट बजट सत्र में ही सदन में पेश कर दी जाती।

एक और बात ध्यान देने योग्य है कि सरकार किसी भी आयोग की सिफारिशों को नहीं मानती है। महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए गठित आयोग हो या सुभाष चंद्र बोस का पता लगाने के लिए गठित आयोग या सांप्रदायिक दंगों की जांच करने वाले आयोग, किसी की भी सिफारिश पूरी नहीं मानी गई। इंदिरा गांधी हत्या की जांच के लिए ठक्कर आयोग बना था। ठक्कर आयोग ने नाम लेकर एक दिग्गज कांग्रेस नेता की ओर इशारा किया था, लेकिन राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने उस कांग्रेसी नेता को अपने साथ रख लिया। वह नेता आज भी कांग्रेस में सम्मान के साथ उच्च स्तर पर विराजमान है।

संसद और सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आयोग इसलिए बनाए जाते हैं, ताकि लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास बढ़े। आम आदमी को यह हक है कि वह आयोगों और उनकी रिपोर्टों की सच्चाइयों को जाने। ■

(लेखक जाने–माने वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भाजपा ने जारी किया घोषणा-पत्र भाजपा का एक रुपये किलो चावल का वादा

झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए हर पेट को भोजन, हर हाथ को काम देने का वादा किया, वहीं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की घोषणा की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास ने प्रदेश मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, अर्जुन मुंडा, सांसद प्रभात झा, संगठन महामंत्री रामलाल, वरिष्ठ नेता पीएन सिंह, यदुनाथ पांडेय, अभयकांत प्रसाद, दीपक प्रकाश, संजय सेठ, प्रदीप सिन्हा समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास ने घोषणा पत्र को पांच सालों के लिए जनता के साथ किया जाने वाला अनुबंध पत्र बताया।

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण के लिए निगरानी की ठोस व्यवस्था होगी। इसके साथ ही राज्य सरकार जन शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर एक आपत्ति निराकरण सेल स्थापित करेगी, ताकि हर स्थिति में आम जनता की शिकायतों का निराकरण निश्चित समय सीमा में हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी का यह मानना है कि वैसे लोक सेवक जिन्होंने आय के स्रोतों से असंगत अकूल संपत्ति भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित कर ली है, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं निषेधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध संपत्ति को राजसात करने, दंडित करने तथा ऐसे मामलों के तेजी से निष्पादन के लिए कठोर कानून बनाएगी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण रखी जाएगी। साथ ही तीन माह के अंदर प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई पेट भूखा न रहे और न कोई हाथ खाली रहे।

घोषणा-पत्र के प्रमुख अंश

सुशासन : भ्रष्टाचारमुक्त झारखंड

- प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार निवारण हेतु निगरानी की ठोस व्यवस्था होगी।
- प्रशासन को पारदर्शी, संवेदनशील एवं लोक प्रतिबद्ध बनाने के लिए कार्यपालिका नियमावली में ठोस उपबंध किये जायेंगे।
- प्रत्येक चुने हुए प्रतिनिधि को प्रति वर्ष जनता के बीच (सोशल ऑडिट) सामाजिक अंकेक्षण के लिए अपने को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- विधायकों क्षेत्र विकास निधि के खर्च का ब्यौरा वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से जनता को देने के लिए सरकार नियम बनायेगी।
- राज्य सरकार जन शिकायत निवारण के लिए प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर एक आपत्ति निराकरण सेल (मैकेनिज्म) स्थापित करेगी ताकि हर स्थिति में आम जनता की शिकायतों का निराकरण समय–सीमा के

अंदर हो सके। इस प्रक्रिया में आई.टी. का उपयोग किया जाएगा।

- झारखंड विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के लिए पूर्व में विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को अमलीजामा पहनाने का प्रयत्न किया जाएगा।
- पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- भाजपा सरकार भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध सम्पत्ति को राज्यसात करने, उसे दंडित करने तथा ऐसे मामलों को तेजी से निष्पादन के लिए कठोर कानून बनाएगी।

असहनीय बेलगाम महंगाई

- केन्द्र की कांग्रेस सरकार सत्ता सम्हालते ही मात्र दो–तीन माह में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में तीन गुनी वृद्धि करवा चुकी है और यह तेजी से बढ़ रही है। परिणाम है कि आमजन की थाली से हरी सब्जी, दाल, चीनी, तेल गायब हो गए हैं।

खाद्यान्न सुरक्षा

- सरकार गठन के तीन माह के अन्दर प्रत्येक परिवार को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुनिश्चित करेंगे कि न कोई पेट भूखा रहे, न कोई हाथ खाली रहे।

बी.पी.एल. हमारी प्राथमिकता

- बी.पी.एल. सूची से वंचित सभी अपेक्षित परिवारों को तीन माह के अन्दर बी.पी.एल. सूची में शामिल किया जाएगा।
- बी.पी.एल. परिवार को 35 किलो अन्न (चावल या गेहूँ) प्रतिमाह 1 रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को 25 पैसे प्रति कि.ग्रा. की दर से नमक मुहैया कराया जाएगा।

कृषि, पशुपालन एवं वानिकी : जीविका के आधार

- किसानों को कृषि कार्य हेतु 2 प्रतिशत व्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाएगा।
- राज्य के किसानों के कृषि ऋण पर सूद (ब्याज) की राशि माफ की जायेगी।
- कृषि बीमा योजना को अधिक प्रभावी एवं सुविधाजनक बनाया जाएगा।
- प्रत्येक किसान को सिंचाई एवं पीने के पानी के लिए कुंआ खोदने हेतु अनुदान दिया जाएगा।
- प्रत्येक जिला में ''किसान बैंक'' और ''अन्नदाता भवन'' बनाया जाएगा।
- कृषि को लाभकारी, रोजगार मूलक एवं उन्नत बनाने के उद्देश्य से "कृषि विकास आयोग" का गठन किया जाएगा।
- 'उन्नत कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम'' के तहत प्रत्येक जिला में किसानों को सम्मानित किया जाएगा।
- किसानों को कृषि एवं बागवानी के सभी उत्पादनों का लाभकारी मूल्य दिलाया जाएगा।
- सरकार गोवंश आधारित कृषि तथा जैविक कृषि को समर्थन देगी।

युवा प्रतिभा विकास

- भाजपा सरकार राज्य में युवा प्रतिभा विकास के लिए ''युवा आयोग'' गठित करेगी एवं सार्वदेशिक विकास के लिए अलग युवा विकास निदेशालय बनाया जाएगा।
- भारतीय जनता पार्टी राज्य की युवा प्रतिभा को रचनात्मक दिशा देने की हिमायती है इस क्रम में गाँव से लेकर शहर तक के वैसे युवक–युवतियों को जो लघु, परंपरागत उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग, स्वरोजगार से स्वांलम्बन के लिए स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए ''वेन्चर कैपिटल फंड'' की स्थापना करेगी।
- ''युवा उद्यमिता विकास'' हमारी प्राथमिकता होगी।
- छोटे–मोटे रोजगार या व्यापार के लिए अधिकतम 25000 रुपये की धनराशि बेरोजगारों को 2 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।

रोजगार सृजन

- पांच वर्षों में दस लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
- कस्बों से राजधानी तक अनुपयुक्त सरकारी भूमि पर बाजार–प्रांगण बनाकर स्वरोजगार–स्वावलम्बन हेतु बेरोजगार युवकों को आवंटित किया जाएगा।
- राज्य को ''हर्बल स्टेट'' (वनौषधि राज्य) के रूप में विकसित किया जाएगा।
- देशज हुनर, शिल्प और हस्तकला को तकनीक से जोड़कर विकसित किया जाएगा और स्वावलम्बन की दिशा में कारगर बनाया जाएगा।
- सभी श्रेणी की सरकारी रिक्तियों को एक साल के अन्दर भरा जाएगा। सरकार नियुक्तियों के लिए उम्र सीमा में आवश्यक छूट देगी।
- सरकार सर्वेक्षण कराकर जिला स्तर पर नियुक्तियों में रोस्टर लागू करेगी।

महिला सशक्तिकरण

- जन्म के एक वर्ष के अन्दर बालिकाओं को ''राज्य लक्ष्मी'' योजना के तहत आच्छादित किया जाएगा। पैदा होने के एक वर्ष के अन्दर उतनी धनराशि उसके नाम से जमा कर दी जाएगी कि जब वह लड़की शादी करने योग्य हो तब लगभग एक लाख से अधिक की धनराशि उसके हाथों में हो।
- महिला सशक्तिकरण योजना के तहत भाजपा सरकार प्रत्येक बालिका को शिक्षित करेगी और उनके समेकित उत्थान के लिये ''बालिका विकास कोष'' स्थापित किया जाएगा।
- किशोरियाँ कल का भविष्य हैं। उनके कुपोषण को दूर करने, एकीकृत योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण आहार, पोषण शिक्षा, एनिमिया पर प्रभावी रोक तथा हुनर–शिल्प से जोड़ने का काम किया जाएगा।
- भाजपा ''नारी सशक्तिकरण'' अभियान के क्रम में ''लाड़ली लक्ष्मी योजना'' अंतर्गत बच्चियों के विद्यालय में सहज पहुँच हेतु वंचित परिवार को छठे वर्ग में रु. 2000/–, नवम वर्ग में 4000/– एवं एकादश वर्ग में 6000/– रुपये की विशेष छात्रवृत्ति देगी। उच्च शिक्षा

प्राप्ति हेतु प्रति वर्ष 7500/– रुपये छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।

- भाजपा सरकार की गरीब बच्चियों की शादी के लिए ''कन्यादान योजना'' को काफी लोकप्रियता मिली थी। हम इसे और अधिक प्रभावी बनायेंगे।
- भाजपा सरकार सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन कर सभी जरुरतमंद तक सामाजिक सुरक्षा लाभ पहुँचायेगी।
- प्रत्येक विधवा एवं परित्यक्ता बहन को अनिवार्य रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगा।
- पुलिस के सशस्त्र बलों में महिला बटालियन का गठन किया जाएगा।

शिक्षा

- प्रत्येक पंचायत में एक उच्च विद्यालय एवं हर प्रखंड में उच्च शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्वित कराई जाएगी।
- झारखंड के सुदूरवर्ती गांवों, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के शिक्षा विहीन बच्चे–बच्चियों को (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदिम जनजाति सहित) शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ''आवासीय मोड'' में गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी।
- राज्य के प्रत्येक प्रमंडल में एक मेडिकल कॉलेज, जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटेकनिक, पारा मेडिकल संस्थान और प्रत्येक अनुमंडल में आई.टी.आई. खोला जाएगा।
- भाजपा सरकार छः माह के अन्दर तकनीकी विश्वविद्यालय (Technical University) एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी।
- उच्चतर तकनीकी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना के नियमों का सरलीकरण किया जाएगा तथा राज्य को ''शिक्षा–हब'' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- झारखंड में आई.आई.एम., आई.आई.टी., राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय, शोध संस्थान सहित राष्ट्रीय मानक के विविध संस्थाओं को स्थापित करने के लिए समस्त ढांचागत सुविधायें प्रदान करायी जाएगीं।
- सरकार संस्कृत भाषा के विकास के लिए संस्कृत महाविद्यालय खोलेगी। सरकार राज्य भर में आध्यात्मिक, नैतिक एवं योग शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करेगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

- सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ''नेशनल रुरल हेल्थ मिशन'' (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन) के कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता, चलन्त स्वास्थ्य इकाई (मोबाइल मेडिकल यूनिट) को प्रभावी बनाते हुए उसे मूल्यांकन एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण से भी जोड़ा जाएगा। इस सेवा को और अधिक लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- ''सभी के लिए स्वास्थ्य'' योजना को भाजपा पब्लिक–प्रायवेट–पार्टनरशिप के तहत कार्य रूप देगी। इसमें बी.पी. एल. का प्रीमियम सरकार द्वारा दिया जाएगा। सभी लाभार्थी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करेंगे।
- राज्य में आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथी एवं योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत एवं आर्थिक समर्थन दिया जाएगा।
- सरकार राज्य में गाँव–गरीब को मेडिकल सुविधाओं से जोड़ने के लिए टेली मेडिसन पद्धति का भी सहयोग लेगी।
- सरकार प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य अभिकर्ता को नियुक्त करने पर विचार करेगी।

कल्याण

- राज्य में निजी एवं व्यावसायिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा किसानों/बेरोजगारों/उद्यमियों आदि को ऋण देने में कोताही बरती जा रही है, परिणाम है कि राष्ट्रीय मानक से ऋण जमा अनुपात बहुत कम है। भाजपा सरकार राष्ट्रीय औसत तक पहुँचाने के लिए बैंकों को लाभार्थियों तक पहुँचायेगी।
- ''बैंक आपके द्वार'' योजना के तहत सभी योजनाओं के सभी लाभार्थियों का बैंक खाता खुलवाया जाएगा।
- 8वें वर्ग से उच्च विद्यालय तक की सभी छात्राओं को सरकार शैक्षिक सुविधा के लिए सायकिल उपलब्ध करायेगी।
- वृद्धावस्था पेंशन की राशि दुगुनी की जाएगी।
- राज्य में अभियान चलाकर एक लाख स्वयं सहायता समूह गठित कराया जाएगा और पूर्व गठित को समृद्ध किया जाएगा।

अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण

- सरकार ''जनजातीय कल्याण योजना'' के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार की आय तीन वर्षों में दुगुना करने का लक्ष्य रखेगी। इसी प्रकार की योजना अनुसूचित जाति के लिए भी चलाई जाएगी।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों के ''बैक लॉग'' को छः माह के अन्दर भरा जाएगा।
- बेरोजगार अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के युवक–युवतियों को स्वरोजगार प्रोत्साहन के लिए 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।
- आदिम जनजाति के 20 से 40 आयु वर्ग के प्रत्येक युवा–युवती को सरकारी रोजगार से जोड़ा जाएगा एवं प्रत्येक सदस्य का बीमा सुनिश्चित कराया जाएगा।
- राजग सरकार ने 22 एवं 23 नवंबर, 2004 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने संबंधी निर्णय के आलोक में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अनुरोध किया था। सरकार इसके लिए पुनः प्रयास करेगी।
- भाजपा सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समेकित विकास के लिए ''अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग'' का गठन करेगी।
- भगवान बिरसा मुंडा भवन बनाया जाएगा जहाँ अनुसूचित

जनजाति के समग्र विकास हेतु शोध केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 को लोकहित में शीघ्र लागू कराया जाएगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग

- सरकार अत्यंत पिछड़े वर्ग के विकास के लिए रोजगार, स्वरोजगार में सहयोग प्रदान करेगी।

श्रमिक कल्याण

- हर हाथ को काम हमारा मंत्र है। काम देने, लेने व करने में स्वयं समर्थ बने, यह सरकारों से ऊपर उठ कर असरदार प्रक्रिया का आकार ले, यह हमारा लक्ष्य है।

मजदूर सुरक्षा योजना

- खेतिहर मजदूरों के कल्याण और सुरक्षा की दिशा में सरकार मुख्यतः कृषि, उद्यानिकी, वानिकी आदि कार्यों में जुड़े रहकर अपना जीवकोपार्जन करने वाले मजदूरों का पंजीयन करायेगी तथा उनकी दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि सहित चिकित्सा, विवाह, प्रसूति आदि में सहायता और मेधावी छात्र पुरस्कार जैसे लाभ देगी।
- सभी असंगठित श्रमिकों के लिए बीमा आदि कल्याणकारी योजनाएँ प्रारंभ की जाएगीं और विभिन्न वर्गों की चौपाल आयोजित कर उनकी समस्याओं का समाधान व विकास की योजनाओं का प्रारूप बनाया जाएगा।

उग्रवाद

- हमारी सरकार न केवल प्रशासनिक अपितु सामाजिक हल भी ढूंढ़ेगी। हम ''उग्रवाद'' मुक्त झारखंड बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे।

ग्रामीण विकास

- भाजपा सरकार कृषि, ग्रामीण विकास एवं सिंचाई के लिए आय–व्ययक में 60 प्रतिशत का उपबंध करेगी।
- ग्रामों में न्याय प्रक्रिया सरल और सुलभ हो तथा वर्षों से लंबित छोटे–छोटे प्रकरणों की समाप्ति शीघ्र करने हेतु 'ग्राम कचहरी' का भी गठन करने की दिशा में विचार किया जाएगा।

पंचायती राज : गांव की सत्ता गांव के हाथ

- पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाना अपरिहार्य है। भाजपा सरकार शीघ्र पंचायत चुनाव कराने के लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने हेतु विधिक प्रयास करेगी।
- सरकार कृषि, उद्योग, ग्रामीण विकास, पीने का स्वच्छ पानी, रोजगार आदि की योजनाओं को बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए ''जनता प्रथम'' कार्यक्रम चलायेगी जिसमें संबंधित विधायक एवं पदाधिकारी गांवों में जाकर जनभावना के अनुकूल कार्रवाई करेंगे।

ढांचागत विकास

- भाजपा इस मत की है कि समग्र विकास के लिये ढांचागत संरचना आधारभूत तत्व है। अतः सरकार भौतिक संरचना अर्थात सड़कें, बिजली, स्वच्छ पीने का पानी, परिवहन सुविधा, वेस्ट मैनेजमेंट, आवास तथा अन्य क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुरूप ढांचागत विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।
- विधानसभा भवन, राज्य सचिवालय, निदेशालय तथा अन्य सरकारी कार्यालय भवनों के शीघ्र निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

ऊर्जा

- हम जरूरत के मुताबिक बिजली मुहैया करा सकें इसके लिए सार्थक प्रयास करेंगे। राज्य की विद्युत उत्पादन इकाईयों के प्लांट लोड फैक्टर में अपेक्षित वृद्धि के लिए उनका अभिनवीकरण किया जाएगा तथा युद्ध स्तर पर उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जाएगी।
- ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्युशन लॉस को न्यूनतम स्तर पर लाने के साथ–साथ ''ओपेन एक्सेस'' पद्धति लागू की जाएगी।
- इलेक्ट्रीसिटी अधिनियम–2003 के अंतर्गत झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को छः माह के अन्दर पुनर्गठित किया जाएगा।
- भाजपा सरकार राज्य में यूरेनियम आधारित परमाणु उर्जा संयंत्र लगाने की पहल करेगी।

स्वच्छपेयजलापूर्ति

- सभी पंचायत भवन के समीप एक–एक चापाकल पेयाजलापूर्ति हेतु लगाया जाएगा एवं कुओं एवं अन्य पेयजल स्रोतों की सफाई करायी जाएगी।
- वाटर ट्रीटमेंट प्लांट युद्ध स्तर पर बनायेगी।
- जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत पीने के पानी की योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा कराया जायेगा।

परिवहन

- प्रत्येक पंचायत को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा तथा सभी गांवों तक पहुँच पथ बनाये जायेंगे।
- पब्लिक–प्रायवेट–पार्टनरशिप के तहत राज्य में आधुनिक बस–टर्मिनल बनाया जाएगा।

पर्यटन विकास

- आंजन ग्राम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- झारखंड में ''पर्यटन'' को राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए "Eco friendly Community based" पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे होने वाली आय उस समुदाय को जाएगा।

शहरी विकास

- भाजपा सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन एवं मलिन बस्ती (स्लम) विकास की योजनाओं को अमलीजामा पहनाकर बेरोजगारी, कुपोषण दूर करायेगी और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वनियोजन को बढ़ावा देगी।

उद्योग एवं व्यापार

- सरकार राज्य में बेरोजगार युवा को उद्यमिता विकास एवं देशज, परम्परागत, कुटीर एवं लघु उद्यम को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिये ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय'' का गठन करेगी।
- जी.एस.टी. को लागू करने के पूर्व सभी पक्षों को विश्वास में लिया जाएगा।

- सरकार स्वकर निर्धारण पद्धति को सही मायने में लागू करायेगी।
- व्यापार–रोजगार से संबंधित लाइसेंस नवीकरण की पद्धति समाप्त की जाएगी।
- सरकार 90 दिनों के अन्दर नयी औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी।
- ''औद्योगिक क्लस्टर'' की स्थापना राज्य के उन सभी क्षेत्रों में की जायेगी जहाँ औद्योगिक विकास की संभावनायें हैं। सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अलग मूल्य निर्धारित करेगी।
- स्वरोजगारी एवं व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की जाएगी।
- सरकार आदर्श एवं अधिकतम करदाता व्यवसायी को प्रति वर्ष ''भामाशाह पुरस्कार'' से सम्मानित करेगी।

पुनर्वास

- भारतीय जनता पार्टी सरकार राज्य में पुर्नवास को विकास के लिए एक अहम् बिन्दु मानती है। सरकार सभी हित पक्षों के समेकित लाभ को ध्यान में रखते हुए सहभागिता के आधार पर ठोस नीति अपनाएगी।

वन-पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

- पर्यावरण संरक्षण के आधार पर राज्य को प्रदूषण मुक्त एवं स्वच्छ बनाया जाएगा।
- तेजी से सिमटते वन क्षेत्र को जन सहभागिता के आधार पर संरक्षित एवं विकसित किया जाएगा। ''वृक्ष लगाओ : वृक्ष बचाओ'' द्वारा वानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य के सभी जिलों में वनौषधि बाग (हर्बल गार्डेन) की स्थापना की जाएगी।
- भूमि संरक्षण के उपाय किए जायेंगे।

खेल : झारखंड की विशिष्ट प्रतिभा

- राज्य में ''खेल एकादमी स्थापित किया जाएगा''–जिसमें सभी खेलों को बढ़ावा मिलेगा तथा उत्कृष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। सरकार विशेष रूप से हॉकी को व्यापक बनाने की पहल करेगी।
- राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों/पूर्व खिलाड़ियों को सरकार नियोजन देने की व्यवस्था करेगी।
- सरकार खेल महाविद्यालयों की स्थापना करेगी।

कला एवं संस्कृति

- भाजपा सरकार झारखंड की लोक कलाओं के गुणात्मक विकास के लिए पहल करेगी और कलाकारों को प्रोत्साहित करेगी।

अल्पसंख्यक विकास

- अल्पसंख्यक वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्वरोजगार एवं स्वावलम्बन हेतु रचनात्मक प्रयास किया जायेगा।
- अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों मदरसा आदि को तकनीकी शिक्षा के साथ जोड़ते हुए उनके पाठ्यक्रम का स्तरोन्नयन किया जायेगा।

सबको आवास

- भाजपा सरकार तीन लाख आवास निर्माण करायेगी।
- आवास निर्माण हेतु प्रचलित बाजार दर पर भूमि की उपलब्धता कानूनी तरीके से सुनिश्चित करायी जाएगी।

आपदा प्रबंधन

- प्राकृतिक आपदाओं वर्षा, सूखा, बाढ़ आदि से निपटने के लिए सरकार ''आपदा प्रबंधन आथोरिटी'' का गठन करेगी।
- आपदा प्रबंधन को सुदूर गाँवों तक पहुँचाने के लिए पंचायतों, ग्राम सभाओं आदि को आवश्यक ढांचागत सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

नि:शक्त

- निःशक्त बच्चों/छात्र–छात्राओं की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं रोजगार की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

संथालपरगना : समेकित विकास की दृष्टि से-

- दुमका में माननीय उच्च न्यायालय, राँची का बेंच शीघ्र स्थापित करने की पहल की जाएगी।
- दुमका में एम्स (AIIMS) की तर्ज पर अस्पताल/मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
- देवघर को केन्द्र मानते हुए संथालपरगना को पर्यटन–हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

सभी भाषाओं को सम्मान

- भारतीय जनता पार्टी यहाँ की नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा, अंगिका, मुंडारी, हो, खड़िया, संताली, कुड़ख, भोजपुरी, उर्दू, बंगला, उड़िया, मैथिली सहित सभी भाषाओं को संरक्षण मिले, इसके लिए उचित कदम उठायेगी। ऐसी भाषायें जो आठवीं अनुसूची में अधिसूचित हैं, उन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल करने की पहल की जाएगी।
- सरकार राज्य में बंगला भाषा को द्वितीय राज भाषा का दर्जा दिलायेगी।

विविध

- 1974 'सम्पूर्ण क्रांति' से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाएगा।
- कैलाश–मानसरोवर यात्रा के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी।
- राज्य में गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा गो वंशीय पशुओं की तस्करी पर प्रभावी रोक लगायी जायेगी।
- भाजपा सरकार राज्य के अधिवक्ताओं की सेवाओं के संवर्द्धन पर विचार करेगी।
- भाजपानीत राजग सरकार ने पूर्व में झारखंड आंदोलनकारियों पर लंबित हजारों मामलों को वापस लिया था। सरकार झारखंड आंदोलन से जुड़े सभी आंदोलनकारियों के ऊपर लंबित मामलों को वापस लेगी। उन्हें सम्मानित करेगी और पेंशन देने पर विचार करेगी।
- भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों की मूल आस्था में विश्वास रखती है। हम बलात, भय या प्रलोभन के माध्यम से हो रहे धर्मांतरण का विरोध करते हैं। भाजपा सरकार इस प्रकार से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनायेगी। ■

झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा : लालकृष्ण आडवाणी

झारखंड में विधानसभा चुनाव–प्रचार जोरों पर है। राज्य की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 25 नवंबर से पांच चरणों में कराए जाएंगे। चुनाव 18 दिसंबर को संपन्न होंगे जबकि मतगणना 23 दिसंबर को होगी। झारखंड में भाजपा, जदयू, कांग्रेस, झामुमो, राजद सहित अनेक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाओं में अपने दल के प्रत्याशियों को जिताने की अपील जनता से कर रहे हैं। भाजपा की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह, बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा, सांसद श्री शत्रुघ्न सिन्हा, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती स्मृति ईरानी सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाओं को संबोधित कर राज्य में कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल रहने का आरोप लगाया और घोषणा की कि भाजपा की सरकार बनने पर राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। भाजपा के सुव्यवस्थित चुनाव–प्रचार से जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी–जदयू गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है और जिस तरह से जनता का पुरजोर समर्थन इस गठबंधन को मिल रहा है, उससे यह तय प्रतीत हो रहा है कि आने वाली सरकार भाजपा–जदयू गठबंधन की होगी। हम यहां भाजपा नेताओं के चुनावी जनसभाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं :

X त 21 नवंबर 2009 को ckdkjk में आयोजित चुनावी जनसभा में श्री लालकृष्ण आडवाणी ने खर्च बचाने के लिए फिर से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की वकालत की। जदयू अध्यक्ष एवं अपने सहयोगी शरद यादव के साथ यहाँ श्री आडवाणी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराना और चुनावी खर्च को घटाना बहुत जरूरी है। मैंने इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी से बात की है। चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए यहाँ आए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि यदि इस संबंध में कोई विधेयक लाया जाता है तो पार्टी इसका समर्थन करेगी। श्री आडवाणी ने झारखंड में कांग्रेस पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल रहने का आरोप लगाया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि झारखंड में जो भी विकास दिख रहा है वह भाजपा शासन की देन है और इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा। श्री आडवाणी ने 22 नवंबर को xkÏk में आयोजित चुनावी सभा में राजद सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के युग में लालटेन से काम नहीं चलने वाला है और केवल भाजपा गठबंधन ही प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि तथाकथित धर्म निरपेक्षतावादियों ने आरक्षण का मामला उठाया था और संपूर्ण देश जब धू–धू कर जल रहा था उस समय उन्होंने समरस समाज के निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली तो उन्हें अविभाजित बिहार के समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार कर हेलीकाप्टर से संथालपरगना के मसानजोर डैम में लाकर रखा गया था। इस कारण उन्हें गोड्डा जिले से अतिशय प्यार है। उन्होंने गोड्डा के प्रबुद्ध जनता की भूरि–भूरि प्रशंसा की तथा उन्होंने विश्वास जताया और कहा कि गोड्डा की जनता उनके गठबंधन के प्रत्याशी को निराश नहीं करेगी।

वरिष्ठ भाजपा नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि राजग ही झारखंड की जनता को राहत दे सकती है। झारखंड में महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। पिछले कुशासन में राज्य की जनता को जो कुछ भी परेशानियां झेलनी पड़ीं, उनसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ही राहत दिला सकती है। श्री आडवाणी 22 नवंबर, 2009 को ckdkjk हवाई अड्डे पर देवघर जाने के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पूरे देश में लोकसभा व विधानसभा का चुनाव साथ–साथ कराये जाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के बाद वर्ष 1952 से लगातार चार आम चुनाव एक साथ हुए। पांचवां चुनाव 1972 में होना था, जबकि उसे 1971

में ही करवाया गया। तब से अलग–अलग चुनाव होने लगे। यह संविधान निर्माताओं की कल्पना नहीं थी। श्री आडवाणी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वह ऐसी व्यवस्था लायें, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ हो सकें। साथ–साथ चुनाव के बहुआयामी फायदे होंगे। इसके लिये संविधान में संशोधन भी करना पड़े, तो किया जाना चाहिये। इस अवसर पर श्री आडवाणी के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव उपस्थित थे।

वरिष्ठ भाजपा नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने 22 नवंबर, 2009 को देवघर/ गोड्डा/ नाला में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की चर्चा देश–विदेश में होती है, तो बस मधु कोड़ा के कारण। मगर मैं कहता हूं कि कोड़ा की आलोचना मत करो। आलोचना करनी है, तो उसकी करो, जिसने निर्दलीय कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया। झारखंड से भ्रष्टाचार मिटाना है, तो मधु कोड़ा को नहीं, बल्कि कांग्रेस को मारो। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गयी है। श्री आडवाणी के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव भी मौजूद थे।

सरकार बनी, तो लुटेरों को जेल भेजेंगे : राजनाथ सिंह

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में भाजपा–जदयू गंठबंधन की सरकार बनी, तो राज्य के लुटेरों–भ्रष्टाचारियों को न केवल जेल में डालेंगे, बल्कि जो राशि लूटी गयी है, उनके मुंह में उंगली डाल कर पेट से निकालेंगे। पता लगायेंगे कि कौन–कौन लोग यहां से स्विटजरलैंड गये और कितनी बार गये। श्री सिंह 22 नवंबर, 2009 को lkdph आम बगान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में झारखंड के लोगों ने राजग को जनादेश दिया था, लेकिन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने साजिश कर निर्दलीयों को खरीद–फरोख्त कर सरकार गिरा दी और एक निर्दलीय को सीएम बना दिया। दरअसल इसके पीछे एक ही मंशा थी कि मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के बहाने राज्य के खजाने को लूट लेना है। श्री सिंह ने सोनिया गांधी के स्थायी सरकार बनाने संबंधी बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं है कि लोकसभा चुनाव में ही झारखंड की जनता राजग को जनादेश दे चुकी है। हम 40 विधानसभा सीटों पर नंबर वन हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों को जीना हराम कर दिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 23 नवंबर, 2009 को xkek में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि मधु कोड़ा प्रकरण के तार दिल्ली से जुड़े हुए है। राज्य में अगर एनडीए की सरकार आयी तो मधु कोड़ा के पेट से झारखंड के लूट का माल बाहर निकाला जायेगा। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मधु कोड़ा तो सिर्फ मुखौटा हैं। उनके साथ लूट में कांग्रेस व उनके सहयोगी दलों की भूमिका की जांच सीबीआई से करायी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के सपनों को मिटने नहीं दिया जायेगा। समय आ गया है कि राज्य की तस्वीर बदलने का। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद राजग और संप्रग के कार्यकालों की तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि राजग ने इस राज्य को क्या दिया और संप्रग के आने के बाद किस प्रकार यह राज्य लूट का शिकार हुआ। अगर राज्य में एनडीए की सरकार आयी तो झारखंड की बेटियों की आशियाना नहीं उजड़ेगा। वर्ग छह की छात्राओं को 2000, नवीं की छात्राओं को 4000, वर्ग 11 की छात्राओं को 6000 हजार रुपये वार्षिक तथा उससे आगे पढ़ने वाली छात्राओं को साढ़े सात हजार रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता दी जायेगी, ताकि छात्राओं की पढ़ाई में उनके विवाह के खर्च का खलल न पड़े। उन्होंने सरकार आने पर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि का लाभ भी लोगों तक पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार आयी तो हम इस बात की भी जांच करायेंगे की स्विस बैंक तक पहुंचने वाले सिर्फ मधु कोड़ा हैं या उनके साथ और भी हैं।

drjkl शहर के रानी बाजार स्थित मैदान में 23 नवंबर, 2009 को चुनावी सभा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में राजग ही स्थायी सरकार दे सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनादेश हमारे पक्ष में आया था, लेकिन कांग्रेस ने खरीद–फरोख्त कर एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बना दिया। मधु कोड़ा ने 4000 करोड़ रुपयों का घोटाला कर देश में इतिहास रच दिया। हम जानते हैं कि कोड़ा ने इतनी रकम अकेले नहीं पचायी है। इसमें कांग्रेस एवं राजद के लोगों की भी भागीदारी है। हम इस मामले पर लोकसभा में उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद श्री राजनाथ सिंह ने आशंका व्यक्त की है कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद मधु कोड़ा भ्रष्टाचार मामले को कांग्रेस की केन्द्र सरकार रफा–दफा कर सकती है। अतः झारखंड की जनता सचेत रहे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में जो 4000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ उसके अपराधी केवल मधु कोड़ा नहीं है, अगर जांच सही ढंग से हो तो इसमें कांग्रेस के लोग भी फंस सकते हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के 22 नवंबर, 2009 को çns'k e[;ky; में खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बोफोर्स दलाली करने वालों को बचाया जा रहा है उसी तरह मधुकोड़ा प्रकरण को भी हाशिए पर डाला जा सकता है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मधुकोड़ा के 4000 करोड़ रुपये के घोटाले को सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र में एनडीए जमकर उठाएगा। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि मधुकोड़ा सरकार के कार्यकाल के दौरान कौन–कौन से नेता स्विटजरलैंड गये। इसका खुलासा होना चाहिए तथा भारतीय जनता पार्टी इसे बेनकाब करेगी।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी–जदयू गठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है और जिस तरह जनता का पुरजोर समर्थन हमारे गठबंधन को मिल रहा है, उससे यह तय प्रतीत हो रहा है कि आने वाली सरकार भाजपा–जदयू गठबंधन की होगी। उन्होंने देश में बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यूपीए

सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण देश में महंगाई तेजी से बढ़ी है। महंगाई के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वह यूपीए सरकार है।

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को पल्लवित किया : रमन सिंह

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 20 नवंबर, 2009 को jkph विधानसभा क्षेत्र में चुटिया के महावीर मुण्डा मैदान में एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों का गठन एक साथ हुआ था और छत्तीसगढ़ आज विकास के पैमाने पर शीर्ष राज्यों की सूची में शामिल है जबकि झारखंड भुखमरी, बदहाली व राजनीतिक अस्थिरता के शाप से ग्रसित निचले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े फर्क का सबसे बड़ा कारण यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर स्थिर व विकासशील सरकार का गठन किया जबकि यहां की जनता कांग्रेस द्वारा फैलाये गए भ्रमजाल में फंसकर रह गयी। कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी ने पूरे देश में भ्रष्टाचार को पल्लवित करने कार्य किया है जिसके कारण ही आजादी के 50 वर्षों के बाद भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

'पहरेदार लुटेरा है तो चारों ओर अंधेरा है' झारखंड के पहरेदार ही लुटेरे हो गये इस स्थिति में राज्य का विकास और इसके निवासियों का कल्याण नहीं हो सकता इस लिये लुटेरों को हटा कर स्वच्छ लोगों को राज्य की बागडोर सौंपे तो झारखंड का चहुंमुखी विकास होगा। उक्त बातें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने 20 नवंबर, 2009 को कही। डा. सिंह uxMh में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डा. सिंह ने कहा कि तत्कालिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी के प्रयास से छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण एक ही समय में हुआ था। छत्तीसगढ़ का विकास उम्मीद से बढ़ कर हुआ परंतु झारखंड जहां कोयला, लोहा, अयस्क, अबरख की बहुतायत है वह पीछे चला गया। इसका कारण एक ही है। यहां के नेतागण जिन्होंने केवल लूटना सीखा। 4000 करोड़ के लूट में सहयोग देने वाला पार्टी को जिताने से राज्य का भविष्य क्या होगा। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लाल कार्ड और पीला कार्डधारियों को क्रमश एक और दो रुपये किलो चावल मिलता है। झारखंड में यही योजना चालू किया जायेगा। महिलाओं के लिए डा. सिंह ने कहा कि छात्राओं के बीच साइकिल तथा विवाह के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहयोग की घोषणा पत्र में जिक्र किया जा रहा है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा रमन सिंह ने 22 नवंबर, 2009 को कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड समान रूप से नक्सल समस्या से ग्रस्त है और इस समस्या का समाधान केंद्र व राज्य की समन्वित योजनाओं से भी संभव है। उन्होंने कहा कि दो दिनों से झारखंड के कई क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया और पाया कि भाजपा के प्रति जनसमर्थन है और इस चुनाव में चालीस से अधिक सीटों पर जीत हासिल होगी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, भाजपा को आठ सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक। ऐसा ही विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिलेगा। भाजपा का घोषणापत्र गरीबों और पिछड़ों के कल्याण में किये जाने वाले कार्यों को रेखांकित करने वाला है। कोई गरीब भूख से न मरे, इसलिए जरूरी है कि उन्हें कम से कम रियायती दर पर दोनों वक्त भोजन मिले। उन्होंने कहा कि झारखंड में कोड़ा एंड पार्टी को झामुमो और कांग्रेस ने समर्थन दिया, इसलिए भ्रष्टाचार के मामले से वे खुद को बरी नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में मीडिया पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए डा सिंह ने निंदा की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव धर्मेंद्र प्रधान, झारखंड भाजपा के वरीय उपाध्यक्ष डॉ दिनेशानंद गोस्वामी भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में झारखंड में व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गयी है। इसके लिए सीधे तौर पर कांग्रेस दोषी है जिन्होंने शिबू सोरेन और मधुकोड़ा जैसे लोगों को मुख्यमंत्री पर काबिज किया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में 21 नवंबर, 2009 को आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने कहा कि यहां की जनता के साथ छल किया गया है। सत्ता भ्रष्टाचार में लिप्त हो गयी और ऐसी सत्ता को कांग्रेस का समर्थन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से देश में झारखंड के प्रति जो दृष्टिकोण बना है, उसे दूर करने की जरूरत है। विकास के लिए झारखंड को स्थायी और स्थिर सरकार की जरूरत है। एनडीए के छह वर्षों के शासन काल में यहां कई योजनाएं लागू की गयी थी। लेकिन जबतक इसका असर दिखता तब तक सत्ता दूसरे के हाथों में चली गयी और झारखंड का विकास रूक गया। डा. रमण ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर झारखंड का समग्र रूप से विकास होगा। नक्सल समस्या के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नक्सली लोकतंत्र के लिए खतरा है। केन्द्र और राज्य सरकारें समेकित कार्ययोजना बनाकर क्षेत्रों का विकास कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। पुलिसकर्मियों को गुरिल्ला वार का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

झारखंड की दुर्दशा के लिए कांग्रेस, झामुमो व राजद जिम्मेवार : सुशील मोदी

बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील कुमार मोदी ने 23 नवंबर, 2009 को कहा कि झारखंड की दुर्दशा के लिये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) जिम्मेवार है। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जब भाजपा छोड़कर गये तो उनके साथ जो समर्थक गये उन्हें आज निराशा हाथ लगी है और वह बड़ी संख्या में भाजपा में लौट रहे हैं। उन्होंने अपील की कि जो लोग अभी भी उनके साथ है वह भाजपा में लौट आये, क्योंकि जिस कांग्रेस को बाबूलाल मरांडी भ्रष्टाचार की जननी कहते थे आज खुद उसी की गोद में जा बैठे हैं। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड की बर्बादी के लिये कांग्रेस, राजद और झामुमो पूरी तरह से जिम्मेदार है और इन्हीं दलों ने ही निर्दलीय मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो रिकार्ड बना उससे ये दल बच नहीं सकते हैं। ■

झारखंड को लूटने वालों का चेहरा बेनकाब होना ही चाहिए : प्रभात झा

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सांसद श्री प्रभात झा ने झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधुकोड़ा के कई हजार के घोटाले पर महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है, जिसका अविकल पाठ हम सुधि पाठकों के लिए नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

महामहिम राष्ट्रपति महोदया
भारत,
नई दिल्ली।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधुकोड़ा की सरकार को सरेआम कांग्रेस, झामुमो एवं राजद ने समर्थन देकर गठन किया और उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया।

मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान श्री मधुकोड़ा ने जो कुछ किया, वह झारखंड की जनता के सामने स्वतः आया है।

हम इस बात में नहीं पड़ना चाहते हैं कि घोटाला छह हजार करोड़ का है या दो हजार करोड़ का। हम तो इतना जानते हैं कि झारखंड का नाम भ्रष्टाचार के मामले में देशभर में ही नहीं विश्व भर में बदनाम हुआ है। झारखंड का अपमान करने का अधिकार किसी हो नहीं है। मधुकोड़ा के घर से एवं ऑफिस से जो कागजात मिले हैं, वह सब जांचकर्ताओं के पास है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि मधुकोड़ा की हवाला डायरी में किन–किन लोगों का नाम है। बस इतना जरूर है कि कल सभी चैनलों और समाचार पत्रों में मधुकोड़ा जी द्वारा यह कहा जाना कि 'मुझे तंग किया तो मैं सब की पोल खोल दूंगा' यह अनेक आशंकाओं की पुष्टि करता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा पर बहुत संगीन आरोप है। राष्ट्र की सम्पत्ति को कौड़ी के भाव बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। झारखंड में जो कुछ भी हुआ है, वह देशवासियों के सामने आना चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय एवं आयकर विभाग को भी इस बात पर जोर देना चाहिए कि श्री मधुकोड़ा ने आखिर यह बात कही तो उसके पीछे कारण क्या है? श्री मधुकोड़ा के गले के नीचे जो नाम है या वे किन–किन लोगों का पोल खोलना चाहते हैं, वह निश्चित ही देश के सामने आना चाहिए।

श्री मधुकोड़ा ने जिस तरह की धमकी दी है, उससे जाहिर होता है कि इस घोटाले से बड़े–बड़े लोगों के तार जुड़े हैं। अतः सबसे पहले श्री मधुकोड़ा की जान–माल की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। वहीं जिस तरह की परेशानी श्री मधुकोड़ा ने व्यक्त की है उससे लगता है कि कहीं वे स्वयं आत्महत्या की दिशा में कदम न उठा लें। अतः मनुष्य के मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं हम सभी जानते हैं कि बिहार के चारा घोटाले में 15 में से 13 गवाह नहीं रहे। वहीं यहां आशंका व्यर्थ नहीं होगी कि कहीं वे प्रभावी लोग, जिनका इस महाघोटाले में नाम है, वे भी हिंसा का सहारा न ले लें। वे कोई राष्ट्र की धरोहर नहीं है पर धरोहर बनकर जिन–जिन लोगों की मार्फत या जिन–जिन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उनकी पोल अवश्य खुलनी ही चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए।

महामहिम, हमारा आपसे आग्रह है कि इस देश में अनेकों घोटाले हुए हैं, पर मुझे जहां तक जानकारी है कि न तो उन घोटालों के आरोपियों का कुछ हुआ न उन्हें सजा मिली। देश का ऐसी बातों से मन खराब हो चुका है। अतः आज यह आवश्यक है कि झारखंड के घोटालों के मसलों से जुड़े उन सभी लोगों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए जो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं।

भारतीय जनता पार्टी इसलिए इस चुनाव में एक ही बात कर रही है कि निर्दलियों से सावधान। स्थिर और बहुमत वाली सरकार के लिए झारखंडवासी वोट करें।

महामहिम, आप संविधान की प्रमुख हैं। संविधान की रक्षा करना आपकी प्राथमिकता है। झारखंड में जो कुछ हुआ है वह संविधान की कुर्सी पर बैठ कर किया गया है। अतः इस बात का खुलासा होना चाहिए कि मधुकोड़ा किन–किन लोगों की पोल खोलना चाहते हैं।

मैं यह पत्र एक जागरूक नागरिक और देश के उच्च सदन का सदस्य होने के नाते लिख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप निश्चित ही इस दिशा में पहल करेंगी।

सादर,

भवदीय
çHkkr >k

कोड़ा मामले में बड़े नेताओं के नाम दबा सकती है कांग्रेस : भाजपा

>kरखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विभागों पर भाजपा ने शंका जताई है। भाजपा के अनुसार जांच कर रहे सभी विभाग केन्द्र सरकार के अधीन है। इसलिए भाजपा को शक है कि भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े कांग्रेस नेताओं को बचाने की हरसंभव कोशिश की जाएगी।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण जेटली के अनुसार झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा की डायरी में अन्य नेताओं के नामों की पूरी सूची है, जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में पैसे खाए हैं। अभी तक दो पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जांच का दायरा जैसे–जैसे बढ़ेगा सब कुछ सामने आ जाएगा। भाजपा के अनुसार कोड़ा की सरकार यूपीए की सरकार थी और यूपीए शासन के दौरान वह भ्रष्टाचार का प्रमुख माध्यम बन चुकी थी। श्री जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार दावा करती है कि सूचना का अधिकार जनता को देश उसकी प्रमुख उपलब्धि थी, तो केन्द्र की सरकार मधुकोड़ा के इस महाभ्रष्टाचार की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करे।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के अधीन जांच एजेंसियों पर शुरू से ही आरोप लगता ही रहा है कि वह केन्द्र के अनुसार अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करती है। भाजपा द्वारा जताई जा रही शंका इस आरोप पर बल प्रदान करने का काम करती है।

क्योंकि केन्द्र में सत्ता का लाभ वो भी उठा चुकी है। इसलिए भाजपा द्वारा कोड़ा के भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विभागों पर शंका जताना साफ उचित करता है कि जांच एजेंसियों पर कितना राजनीतिक दखल होता है। ■

किसी गुप्त एजेंडे पर काम कर रहे थे कोड़ा : अर्जुन मुंडा

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि मधु कोड़ा किसी गुप्त एजेंडे पर काम कर रहे थे। उन्हें समर्थन देने वाले दलों को बताना चाहिए कि वह गुप्त एजेंडा क्या था। श्री मुंडा ने एक समाचार–पत्र के साथ खास बातचीत में कहा कि झारखंड का मूल संकट यहां की राजनीतिक अस्थिरता है। श्री मुंडा के अनुसार इस चुनाव में जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ स्थायी सरकार बनाने के लिए जनादेश देने का मन बना लिया है। श्री मुंडा के अनुसार यूपीए के नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस मजबूरी के तहत उन्होंने एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाकर भ्रष्टाचार का एक नया इतिहास रचा। इसमें कांग्रेस तथा राजद जैसी पार्टियां भी हिस्सेदार हैं।

श्री मुंडा के अनुसार भाजपा जनमुद्दों पर चुनाव लड़कर झारखंड को एक भरोसेमंद सरकार देगी। श्री मुंडा ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार में बैठे लोगों ने ही झारखंड को लूटने तथा विकास को अवरूद्ध करने का काम किया है। इस तरह झारखंड को दिशाभ्रमित कर दिया गया है। कांग्रेस, झामुमो और राजद के समर्थन से बनी सरकार ने राज्य को खोखला कर दिया है। अब उस सरकार के पाप से भला उसे समर्थन देने वाले दल अपना हाथ कैसे छुपा सकते हैं।

श्री मुंडा के अनुसार 2005 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने किसी निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं बल्कि भाजपा की सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया था। लेकिन हमारी सरकार को साजिश के तहत गिराकर किसी गुप्त एजेंडे के जरिये मधुकोड़ा की निर्दलीय सरकार बना दी गयी। इसके क्या दुष्परिणाम हुए, यह जगजाहिर है। यह पूछे जाने पर कि राज्य में भ्रष्टाचार की कोड़ा संस्कृति के विकास में भाजपा का कितना हाथ है, श्री मुंडा ने कहा कि राज्य में निर्दलीय सरकार के गठन के साथ ही कोड़ा संस्कृति की बुनियाद रख दी गयी और इसे समर्थन देने वाले लोग इसके हिस्सेदार हो गये। यह पूछे जाने पर कि इस बार भी त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति में आप झामुमो का समर्थन लेंगे अथवा नहीं, श्री मुंडा ने कहा कि ऐसी नौबत नहीं आयेगी और भाजपा के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। ■

कांग्रेस सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों के चलते

बेलगाम हुई महंगाई

fnल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री विजय गोयल और श्री मदन लाल खुराना और पूर्व प्रदेश भाजपाध्यक्ष डॉ. हर्ष वर्धन ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि मंहगाई से परेशान आम नागरिक की परेशानी न बढ़े इसलिए आवश्यक सेवाओं और परिवहन को बंद के दायरे से मुक्त रखा गया है।

गत 12 नवंबर को नई दिल्ली में एक प्रेस कान्फ्रेंस को सम्बोधित करते हुए उक्त भाजपा नेताओं ने अभूतपूर्व महंगाई को रोकने में केन्द्र की यूपीए सरकार और दिल्ली की कांग्रेस सरकार की घोर उदासीनता और विफलता के लिए कड़ी आलोचना की। उन्होंने सरकार पर मुनाफाखोरी और जमाखोरी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के बयानों को महंगाई के मामले में पल्ला झाड़ने और महंगाई को बढ़ावा देने वाला बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली सरकार एक दिन डीटीसी के बढ़ाए गए भाड़े में मामूली सी कमी करती है और अगले दिन ही मैट्रो के किराए में दो रूपए से लेकर आठ रूपए तक वृद्धि कर देती है। यह सरकार का दिल्लीवासियों से भद्दा मज़ाक है।

भाजपा नेताओं ने कहा कि 15वीं लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही सरकार पूरी तरह निरंकुश हो गई है और महंगाई पर नियंत्रण रखने के मामले में उसने पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। यही नहीं पिछले कुछ महीनों से दिल्ली सरकार ने स्कूलों की फीस बढ़ाने से लेकर मैट्रो के किराए बढ़ाने तक ऐसे आधा दर्जन जनविरोधी फैसले किए हैं, जिनकी वजह से आम दिल्लीवासी आर्थिक बोझ से कराह रहे हैं।

भाजपा नेताओं ने महंगाई के लिए कांग्रेस सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे फैले हुए कारोबारी शहर में जहां लोगों को रोजगार, शिक्षा आदि के लिए दिन भर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर ही वे ज्यादातर निर्भर करते हैं, लेकिन सरकार ने सार्वजनिक परिवहन – बस और मैट्रो – को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है।

भाजपा नेताओं ने मांग की कि :-

- डीटीसी और मैट्रो के बढ़े हुए किराये वापस लिए जायें।
- चीनी घोटाले की जांच कराई जाए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत किया जाए और सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जायें।
- वायदा बाजार के घातक दुष्परिणामों की समीक्षा की जाए और उस पर रोक लगाई जाए।
- सार्वजनिक परिवहन को सस्ता, सुलभ और कुशल बनाया जाए।

महंगाई केन्द्र का सबसे बड़ा घोटाला : भाजपा

भाजपा ने देश में बढ़ती हुई महंगाई को यूपीए सरकार का बसे बड़ा घोटाला बताया है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने दलालों और सट्टेबाजों को देश को लूटने की खुली छूट दे दी है, क्योंकि सत्ताधारी दल ने इनसे चुनावी फंड लिया था। पार्टी ने महंगाई के खिलाफ देशभर में आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि खाद्य क्षेत्र में मूल्य वृद्धि संप्रग सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके तहत सट्टेबाजों को खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हेराफेरी करके देश को लूटने की खुली छूट मिल गई है। यह घोटाला खाद्य पदार्थों वास्तविक अभाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह जमाखोरी और वस्तु विनिमय के माध्यम से मूल्यों के 'जैकिंग अप' का मामला है। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है और सट्टेबाज फल–फूल रहे हैं। सरकार मूकदर्शक बनी हुई है और इस बारे में कोई गंभीर कार्रवाई करने में किसी तरह की रूचि नहीं दिखा रही है। सरकार के पास मूल्यों को कम करने के लिए किसी तरह की राजनीतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि सत्ताधारी दल ने इन सट्टेबाजों से भारी मात्रा में चुनावी फंड प्राप्त किया था। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस को यह नहीं सोचना चाहिए कि हाल की चुनावी सफलता से उसको मूल्य वृद्धि करने का जनादेश प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि जहां सारे विश्व में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी हो रही है, वहीं भारत में इनमें 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह भी एक विरोधाभास है कि चीनी 40 रूपए और गुड़ 50 रूपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है।

पार्टी ने चीनी घोटाले की सीबीआई द्वारा जांच कराने, खाद्यान्न वस्तुओं के संग्रह संबंधी नियमों को संशोधित करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत कर उसके माध्यम से दालों, खाद्य तेलों, गेहूं, चावल और चीनी की आपूर्ति उचित मूल्य पर कराने, दीर्घकालिक मूल्य और विपणन नीति की घोषित करने और वस्तु विनिमय के माध्यम से मसालों सहित सभी खाद्य वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगाने की मांग की है।

महंगाई के मोर्चे पर कांग्रेस की नीतियां बेकार साबित हुईं : नरेन्द्र सिंह तोमर

Hkkपाल 19 नवम्बर, 09/ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि आर्थिक विशेषज्ञ प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह की लाप नीतियों से महंगाई के करंट ने आम आदमी की गृहस्थी को झटके देने शुरु कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के मोर्चे पर कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार बेजार साबित हुई है। इस पर भी केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने भी जले पर नमक छिड़कते हुए पल्ला झाड़ लिया है कि नई फसल से पूर्व महंगाई घटने के आसार नहीं है।

नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि गत साढ़े पांच वर्षों में खाद्य पदार्थों के दामों में 100 से 150 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इस कदर हुई है कि आम आदमी की तो दाल तक नहीं गल रही है। एक साधारण आदमी का जीना दुश्वार हो रहा है। हर किसी का बजट बिगड़ गया है। देश का हर नागरिक महंगाई से त्रस्त है। महंगाई की मार से इंसान कराह रहा है। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी के लिए साधारण सी दाल रोटी खानी मुश्किल हो गई है। एक गरीब आम इंसान के लिए पहले तो यही सुना था कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ परन्तु महंगाई के हालात देखते हुए यही कह सकते हैं कि दाल रोटी सूंघो प्रभु के गुण गाओ।

नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री के बयान के कारण सीधे–सीधे व्यापारियों को ला पहुंच रहा है। उनके इस बयान के कारण गेहूं, चावल के भाव में एकदम तेजी आ गई है। उन्होंने कहा कि अब लोगों के लिए जिंदा रहना सबसे यादा महंगा होता जा रहा है।

नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियां ही सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की परिचायक होती है, जो मुद्रास्फीति व संकुचन पर नियंत्रण स्थापित कर देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करती है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती मुद्रास्फीति ने महंगाई का बोझ आम आदमी पर इतना बढ़ा दिया है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वयं को असमर्थ पाता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की लचर दंड व्यवस्था के चलते जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी जैसी अवांछनीय क्रियाएं महंगाई को बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं।

बाकी कुछ बचा नहीं, महंगाई मार गई

हर बार की तरह सरकार महंगाई की लगाम कसने की बात कहती रही है परन्तु महंगाई सुरसा के मुख की तरह बढ़ती ही जा रही है और लोग लाचार, बेबस होकर सिर्फ सरकारों को कोसते रहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। गरीब आदमी को छोड़ो अब तो मध्यम वर्ग की कमर भी टेढ़ी होने लगी है। कई तरह के खर्चों के बोझ तले दबा मध्यम वर्ग अब महंगाई के कुचक्र में फंस कर तलहटी तक पहुंच गया है, जहां से ऊपर उठ पाने की शक्ति जुटा पाने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा है।

आम आदमी की थाली में निवाला कम होता जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 100 से 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पहले कहते थे दाल–रोटी खाकर गरीब आदमी अपना गुजारा चला लेता था परन्तु कोई भी दाल अब 50 से 100 रूपए किलो से नीचे नहीं है इसलिए दाल अब अमीरों का खाना बन गई है। गरीब बेचारा दाल कैसे खा सकता है। आलू को सी सब्जियों में डालकर बनाया जा सकता है परन्तु आलू भी अब गरीबों को दुत्कारने लगा है। पहले चार–पांच रूपए किलो का आलू अब 30 रूपए किलो मिलता है तो बेचारे गरीब आदमी का साथ आलू ने भी छोड़ दिया लगता है।

आम आदमी सब्जी नहीं मिलने की सूरत में भरपेट रोटी खाकर पानी पी लेता था परन्तु अब आटा भी 20 से 25 रूपए किलो पर जा पहुंचा है। महंगाई से त्रस्त गरीब आदमी अब रोटियां भी गिन–गिन कर खाता है। अन्य सब्जियों और फलों का स्वाद तो गरीब आदमी जानता ही नहीं। महंगाई ने गरीब आदमी को तो पूरी तरह मार ही डाला है। मध्यम वर्ग की भी कमर तोड़ दी है। मध्यम वर्ग अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने की कोशिश में मारा–मारा फिर रहा है। आज सब्जियों में टमाटर 25–30 रूपए, गाजर 35–40 रूपए, शिमला मिर्च 40–50 रूपए, तोरी 30–35 रूपए, बैंगन 15 से 20 रूपए, मेथी 20–25 रूपए, हरा साग 25–27 रूपए, भिंडी 40 रूपए किलो मिल रही है।

पहले बेफिक्र होकर खाने–पीने वाला मध्यम वर्ग अब खाना बनाने से पहले जेब को देखकर सब्जियां खरीदता है। फलों को खरीदना आज मध्यम वर्ग के लिए भी मुश्किल भरा कार्य है। संतरा 40–50 रूपए, अनार 80–120 रूपए, शरीफा 60–70 रूपए, से 80–120 रूपए, चीकू 40–60 रूपए, पपीता 20–25 रूपए किलो मिल रहा है, जो खरीदना हर किसी के बस में नहीं है। बढ़ती महंगाई को देखकर लगता है अब भारत में केवल अमीर ही रह पाएंगे। गरीब आदमियों को कोई दूसरा देश ढूंढना पड़ेगा।

इस देश की सौ करोड़ गरीब जनता की परेशानियों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को केवल वही लोग नजर आ रहे हैं जो अच्छा 'कमा' लेते हैं, परन्तु सरकार भूल जाती है कि अच्छा 'कमाने' वाले लोग कुछ ही हैं बाकी जनता तो भूखों मरने के कगार पर आ गई है।

बेलगाम महंगाई के विरोध में भाजपा का ''दिल्ली बंद'' पूर्ण सफल

Xत 13 नवम्बर को दिल्ली में आयोजित महंगाई के विरोध में भाजपा का 'दिल्ली बंद' चौतरफा, शांतिपूर्ण और पूर्ण सफल रहा। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली ने बंद की सफलता के लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने विशेष रूप से व्यापारियों, दुकानदारों, मज़दूरों, उद्योग क्षेत्र के संगठनों और छात्रों को बंद का भरपूर समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया।

प्रो. कोहली ने कहा कि भाजपा के 'दिल्ली बंद' की खास विशेषता यह थी कि यह पूर्णतया शांतिपूर्ण रहा। इसमें न हिंसा और तोड़फोड़ थी और न ही किसी प्रकार का दबाव। जनता के मन में महंगाई के विरूद्ध जो गुस्सा संचित है, उसे मुखरित करना इस बंद का उद्देश्य था। जनता परेशान न हो, इसे ध्यान में रखकर भाजपा ने आवश्यक सेवाओं और परिवहन को बंद के दायरे से बाहर रखा था।

पूरी दिल्ली में सभी क्षेत्रों में भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश नेताओं और स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में टोलियां बनाकर हाथ में झंडे लेकर और गले में महंगाई विरोधी तख्तियां डालकर बाजारों और सड़कों पर मार्च करते हुए निकले और लोगों से 'दिल्ली बंद' की अपील की। जगह–जगह चौराहों पर मंहगाई और दिल्ली सरकार का पुतला फूंका गया। पूर्वी दिल्ली में गुरूतेग बहादुर अस्पताल में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पहुंची तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया।

प्रदेश के जिन नेताओं ने जगह–जगह पर 'दिल्ली बंद' के अभियान का नेतृत्व किया, उनके नाम हैं : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष प्रो. ओम प्रकाश कोहली, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, भाजपा के अखिल भारतीय महामंत्री श्री विजय गोयल, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन और श्री मांगेराम गर्ग, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के पूर्व नेता प्रो. जगदीश मुखी, नगर निगम में दल के नेता सुभाष आर्य, प्रदेश भाजपा के महामंत्री रमेश बिधूड़ी, आर.पी. सिंह,

'दिल्ली बंद' की खास विशेषता यह थी कि यह पूर्णतया शांतिपूर्ण रहा। इसमें न हिंसा और तोड़फोड़ थी और न ही किसी प्रकार का दबाव। जनता के मन में महंगाई के विरूद्ध जो गुस्सा संचित है, उसे मुखरित करना इस बंद का उद्देश्य था। जनता परेशान न हो, इसे ध्यान में रखकर भाजपा ने आवश्यक सेवाओं और परिवहन को बंद के दायरे से बाहर रखा था।

प्रवेश वर्मा, प्रदेश मंत्री आशीष सूद और सतीश उपाध्याय, प्रदेश कोषाध्यक्ष और व्यापारी नेता प्रवीन खंडेलवाल।

'दिल्ली बंद' कराने में भाजपा के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और किसान मोर्चा के अध्यक्षों अनुज शर्मा, सरिता चौधरी, आतिफ रशीद और राज कुमार बल्लन की महत्वपूर्ण भूमिका रही जिन्होंने अपने–अपने मोर्चो के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए बाजारों में जुलूस निकाले।

विभिन्न क्षेत्रों में भाजपा के अलग–अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 'दिल्ली बंद' कराने का मोर्चा संभाला। ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, ओ.पी. शारदा और अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह ने, करोलबाग में अनिता आर्य, योगेन्द्र चांदोलिया और पार्षद मंजीत कौर बख्शी ने, पश्चिमी दिल्ली और नजफगढ़ क्षेत्र में जगदीश मुखी और सुभाष आर्य ने, दिल्ली के ग्रामीण इलाके में प्रवेश वर्मा, विनोद सहरावत और नील दमन खत्री ने, दक्षिण दिल्ली के महरौली– बदरपुर– कालकाजी– तुगलकाबाद क्षेत्र में आजाद सिंह, सरिता चौधरी और डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता ने, शाहदरा विकास मार्ग क्षेत्र में डॉ. हर्ष वर्धन, रवि शर्मा, पार्षद बी. बी. त्यागी और लता गुप्ता ने तथा उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में मोहन सिंह बिष्ट, नरेश गौड़ और श्रीकृष्ण त्यागी ने तथा किराड़ी क्षेत्र से विधायक अनिल झा ने अपने–अपने क्षेत्रों में दिल्ली बंद का नेतृत्व किया।

स्थानीय स्तर पर भाजपा के जिलाध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, विधायकों और निगम पार्षदों ने मंहगाई विरोधी जुलूसों का नेतृत्व किया और बड़ी संख्या में उनके नेतृत्व में कार्यकर्ता क्षेत्र में बंद कराते रहे।

दिल्ली के सभी प्रमुख बाजार बंद रहे। अजमलखाँ रोड, राजेन्द्र नगर, पटेल नगर, कमला नगर, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, आर.के. पुरम, खजूरी, सीलमपुर, करावल नगर रोड, बाबरपुर रोड, जनकपुरी, तिलक नगर, उत्तम नगर, नजफगढ़, मालवीय नगर, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर, कालकाजी, महरौली, बदरपुर, रोहिणी, बुद्ध विहार, आदर्श नगर, इन्दिरा नगर, आजाद नगर, शालीमार बाग, पीतमपुरा, अशोक विहार, नरेला मंडी, जहांगीरपुरी,

यूसुफ सराय, हौजखास, ग्रीन पार्क और सफदरजंग क्षेत्र जैसे सभी बड़े बाजार पूरी तरह बंद रहे।

दिल्ली के सबसे बड़े व्यापारिक क्षेत्र चांदनी चौक और सदर बाजार पूरी तरह बंद रहे। इन क्षेत्रों में हलवाइयों, पान बेचने वालों और रेहड़ी पटरी वालों ने भी अपना कारोबार बंद रखकर बंद को समर्थन दिया।

चांदनी चौक जिला के मुस्लिम बहुल इलाके तथा यमुनापार के मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके पूरी तरह बंद रहे। चांदनी चौक में बंद का नेतृत्व विजय गोयल, मदन लाल खुराना, प्रवीन खंडेलवाल और मनोहर लाल कुमार ने किया।

कनॉट प्लेस क्षेत्र में प्रारम्भ में दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करने में हिचकिचाहट दिखाई लेकिन भाजपा के युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चाध्यक्ष अनुज शर्मा, रमेश बिधूड़ी, आर.पी. सिंह, आशीष सूद, कुलवन्त राणा, महक सिंह आदि के नेतृत्व में हज़ारों की संख्या में कनॉट प्लेस के भीतरी और बाहरी घेरे में जुलूस निकाला और दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने की अपील की। ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के करीब कनॉट प्लेस के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें बंद करनी शुरू कर दी और देखते देखते कनॉट प्लेस तथा जनपथ भी बंद हो गए।

प्रो. कोहली ने कहा कि आज के 'दिल्ली बंद' ने यह सिद्ध कर दिया कि आम जनता के मन में महंगाई के विरोध में जबरदस्त रोष है और वे केन्द्र की यूपीए सरकार और दिल्ली की कांग्रेस सरकार को महंगाई के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं।

कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियां और आर्थिक प्रबंधन का चरमराना इसके लिए जिम्मेदार है। प्रो. कोहली ने सरकार को चेतावनी दी कि जनता अब अधिक देर तक शांत नहीं बैठ सकती और यदि सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों की दिशा न बदली तो जनरोष बेकाबू भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी महंगाई के विरोध में निरन्तर जनता के साथ खड़ी रहेगी और आने वाले दिनों में जनरोष को मुखरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी।■

संप्रग शासन में खाद्य पदार्थों के मूल्य चढ़े आसमान पर : जावडेकर

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा 11 नवम्बर, 2009 को जारी प्रेस वक्तव्य

[kk द्य क्षेत्र में मूल्य वृद्धि संप्रग सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसके तहत सट्टेबाजों को खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हेराफेरी करके देश को लूटने की खुली छूट मिल गई है। यह घोटाला खाद्य पदार्थों के वास्तविक अभाव से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह जमाखोरी और वस्तु विनिमय के माध्यम से मूल्यों के जैकिंग अप (Jacking up) का मामला है। यह ऐसी स्थिति है, जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है और केवल सट्टेबाज ही फल–फूल रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और इस बारे में कोई गंभीर कार्रवाई करने में किसी तरह की रूचि नहीं दर्शा रही है। सरकार के पास मूल्यों को कम करने के लिए किसी तरह की राजनीतिक इच्छा नहीं है, क्योंकि शासक दल ने इन सट्टेबाजों से भारी मात्रा में चुनावी फंड प्राप्त किया था। कांग्रेस को यह नहीं सोचना चाहिए कि हाल की चुनावी सफलता से उसको मूल्य वृद्धि करने का जनादेश प्राप्त हो गया है। भाजपा सरकार को चेतावनी देती है कि यदि सरकार मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने में विफल रहती है तो उसे लोगों का भारी कोपभाजन बनना पड़ेगा।

यह विडंबना ही है कि जहां सारे विश्व में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कमी हो रही है वहीं भारत में इनमें 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है। यह भी एक विरोधाभास है कि जबकि चीनी 40 रूपए प्रति कि.ग्रा. और गुड़ 50 रूपए प्रति कि.ग्रा. बिक रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक अपनी खड़ी फसल को इसलिए जला रहे हैं कि उन्हें इसके लाभदायक मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति के लिए संप्रग सरकार की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। गत वर्ष कृषि मंत्रालय ने घोषित किया था कि चीनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सरकार ने तब यह अच्छी तरह जानते हुए चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी कि इस वर्ष चीनी की आपूर्ति कम होगी। इस निर्णय के परिणामस्वरूप हमने 48 लाख टन चीनी का 12 रूपए प्रति कि.ग्रा. के मूल्य पर निर्यात कर दिया और उसके बाद के 6 महीनों के दौरान ही हमको 70 लाख टन चीनी 27 रूपए प्रति कि.ग्रा. पर आयात करनी पड़ रही है। यह ऐसा घोटाला है, जिसकी जांच सीबीआई से कराए जाने की आवश्यकता है।

संप्रग सरकार ने खाद्य तेलों में भारत की आत्मनिर्भरता को खत्म कर डाला और उसे पूरी तरह आयात–निर्भर देश बना डाला है। आज हमारा देश अपनी जरूरत का 50 प्रतिशत खाद्य तेल आयात कर रहा है, जो मुख्यतः मलेशिया से किया जा रहा है। संप्रग सरकार देश में खाद्य तेलों की खेती को और खाद्य तेल उद्योगों को नष्ट करने की दोषी है। संप्रग सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ध्वस्त कर दिया और गरीबों के लिए खाद्यान्न की मात्रा को प्रति मास 35 कि.ग्रा. से घटाकर 15–20 कि.ग्रा. कर दिया। संप्रग सकार ने प्राइवेट कंपनियों को किसानों से सीधे खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देकर उन्हें मुनाफाखोरी और जमाखोरी करने का खुला अवसर दे दिया।

भाजपा की मांग

- चीनी घोटाले की सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए।
- खाद्यान्न वस्तुओं के संग्रह संबंधी नियमों को संशोधित किया जाए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इमदाद देकर उसके माध्यम से दालों, खाद्य तेलों, गेहूँ, चावल और चीनी की आपूर्ति उचित मूल्य पर कराई जाए।
- सरकार दीर्घकालिक कृषि मूल्यन और विपणन मूल्यन नीति की घोषणा करे।
- वस्तु विनिमय के माध्यम से मसालों सहित सभी खाद्य वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगाई जाए। ■

महंगाई से गृहणियां सबसे अधिक प्रभावित : सुमित्रा महाजन

Hkkरतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का विशाल मातृशक्ति सम्मेलन 17 नवम्बर को भोपाल स्थित बास्केटबाल काम्पलेक्स में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संपूर्ण बास्केबाल काम्पलेक्स महिलाओं से खचा–खच भरा हुआ था हजारों की संख्या में उपस्थित महिलाओं में सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह था कई महिला मोर्चा की कार्यकर्ता अपने साथ बड़ी संख्या में महिलाओं को लेकर पहुंची थी। सम्मेलन के प्रारंभ में वन्देमातरम् गान हुआ। इसके पश्चात कार्यक्रम का विधिवत् शुभारंभ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्रसिंह तोमर, सांसद सुमित्रा महान, कृष्णमुरारी मोघे, सत्यनारायण सत्तन, बाबूसिंह रघुवंशी, महेन्द्र हार्डिया, सुदर्शन गुप्ता, रमेश मेंदोला, अंजू माखीजा, मालिनी गौड, गोपीकृष्ण नेमा, डॉ. उमाशशि शर्मा, मधु वर्मा, शशि खंडेलवाल, उषा ठाकुर, पदमा भोजे, वीणा वर्मा, कमालभाई, उमेश शर्मा, मुकेशसिंह राजावत, सूरज कैरो, संतोष वर्मा, कल्याण देवांग, हरप्रीतसिंह बक्षी, शांता भामावत, ज्योति तोमर, हेमंत मेहतानी, जवाहर मंगवानी, राकेश शर्मा, प्रकाश पारवानी, स्मिता हार्डिकर, परमानंद राठौर, महेन्द्र भाटिया, आलोक दुबे ने दीप प्रज्वलित कर किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिंह तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को राजनीति में उपस्थिति और भागीदारी उनकी सफलता की प्रतीक है। आज बहने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश व नगर के विकास में सहभागी है। राजनीति क्षेत्र में कार्य करने के लिये आकांक्षा आवश्यक है। यहां उपस्थित महिला बहनों की आकांक्षा पूर्ण हो सके इस हेतु भाजपा ने महिलाओं को नगरीय निकाय चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया।

पूर्व में महिलाएं किसी भी निकाय या सदन में जाने के इच्छुक रहती थी लेकिन जा नहीं सकती थी आज स्थिति परिवर्तित हो गई है। आज पंचायती राज में 4 लाख में से 2 लाख महिला बहनों को टिकट मिलेगी और वे विजय होकर प्रदेश के विकास में सहभागी बनेगी और यह निश्चित रूप से हमारे लिये गर्व की बात है। भाजपा प्रारंभिक काल से ही महिलाओं की हितैषी रही है। अन्य राजनीतिक दलों का महिला मोर्चा दिखाई नहीं देता, लेकिन भाजपा का महिला मोर्चा हिन्दुस्तान के अन्य राजनीतिक दलों से सशक्त है। महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिले इस हेतु हमें प्रयास करना है कि नगरीय निकाय चुनाव में महिला बहने अधिक से अधिक संख्या में अपनी विजय दर्ज करायें और साथ ही अन्य पुरूष सीटों पर महिला बहनें अपने मतदान के माध्यम से उनकी जीत सुनिश्चित करें।

आज सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ''अब तो बराबर की भागीदारी राष्ट्र निर्माण के लिये प्रतिबद्ध है नारी'' इस नारे को भाजपा ने चरित्रार्थ किया है। आज हमारी बहनों को इस बात का संकोच नहीं है कि उसे अपनी बात कहने के लिये कैसे जाना होगा। इंदौर की सांसद, महापौर, विधायक, पार्षद महिलाएं है। इससे आम महिला को अपनी बात कहने में झिझक नही होती है, यह भाजपा ने कर दिखाया है। आगामी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। आज महंगाई बढ़ी है और वह कांग्रेस समर्थित यूपीए सरकार की देन है। भाजपा ने प्रदेश ही नहीं देश में भी विकास कार्य किये अटलजी के शासनकाल में देश–प्रदेश व इंदौर में कई विकास कार्य हुए है। भाजपा अपने देश को मां के समान प्रेम करती है अब महिलाएं तैयार हो जाये अपने अधिकार के लिये मेरा देश, मेरा प्रदेश और मेरे इंदौर की भावना जागृत कर विकास को समर्थक करना होगा।

भाजपा वरिष्ठ नेता श्री कृष्णमुरारी मोघे ने मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस समर्थित केन्द्र सरकार की नीतियों के चलते आज महिलाओं का आत्मरक्षण विगत 4 वर्षो से लंबित है। परन्तु हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने पहले संगठन में 33 प्रतिशत आरक्षण एवं बाद में नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये व बधाई के पात्र है। दोनों बार नगरीय निकाय चुनाव में हमारी बहनों ने विजय हॉसिल की है उनके उत्साह और जागृति को देख कर लगता है कि हम नगरीय निकाय चुनाव में पुनः विजय होंगे और बचे हुए विकास कार्यों को पूर्ण करेंगे।■

साभार : रा. पत्रिका

सरकार संरक्षित गुंडाराज

& ân;ukjk;.k nhf{kr

ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। थप्पड़ महाराष्ट्र विधानसभा के एक सदस्य के गाल पर पड़ा, लेकिन चोट से समूचे राष्ट्र का सिर झन्ना गया है। तमाचा संविधान पर था, राष्ट्रभाषा पर था, सदन की मर्यादा पर था और भारतीय संस्कृति की जुबान हिंदी पर था। सो पूरा राष्ट्र गुस्से में है। यह गुंडाराज अचानक नहीं उभरा। इसको महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार ने ही भरपूर सब्सिडी दी, पाला पोसा। गरीब मजदूरों को लठियाया गया, ठेलिया वाले यूपीए बिहारी, बंगाली गरीबों को मारा। इस दफा उसने ऐलानिया धौंस दी कि सदन में हिंदी में शपथ लेने वालों को ठीक कर देंगे। उसके सहयोगी मान्यवरों ने फिर से पराक्रम दिखाया और सदन गुंडागर्दी का शिकार हुआ। भारत की संविधानसभा में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने पर बहस थी। मुंबई के ही एक सदस्य बीएम गुप्ते ने कहा था कि शीघ्र ही वह दिन भी आएगा जब हिंदी न केवल राजभाषा के पद पर, बल्कि राष्ट्रभाषा के पद पर भी प्रतिष्ठित होगी। मुंबई के ही डा. अंबेडकर सहित अनेक वरिष्ठ नेता सभा में मौजूद थे, लेकिन गुप्ते की उम्मीद को इसी सूबे के 'मनसे विधायकों' ने धराशायी कर दिया।

संविधान निर्माण के समय हिंदी को लेकर उत्तर–दक्षिण और पूरब–पश्चिम के मतभेद नहीं थे। संविधान सभा में सेठ गोविंद दास ने एक सहमति पत्र का जिक्र किया कि इसमें हिंदी राष्ट्रभाषा के पक्ष में निजलिंगप्पा, जेठे, पाटस्कर और गुप्ते, असम के रोहिणी कुमार, चलिहा, उड़ीसा के बी. दास, युधिष्ठिर सिंह आदि व बंगाल के श्रीमैत्र, मजूमदार, सुरेंद्र मोहन घोष आदि के हस्ताक्षर हैं। उन्होंने कोलंबो से लिखा गया नेहरू का पत्र भी पढ़ा–''हिंदी का राष्ट्रभाषा होना पूरी तौर पर तय हो गया है, खुशी की बात है कि तमिलनाडु में हिंदी का प्रचार हो रहा है।'' नेहरू ने संविधान सभा में कहा कि हमने अंग्रेजी स्वीकार की कि वह विजेता की भाषा थी, इस कारण नहीं कि वह एक महत्वपूर्ण भाषा है। अंग्रेजी कितनी ही अच्छी क्यों न हो, हम इसे सहन नहीं कर सकते। गाधी–नेहरू ने संविधान निर्माण के पहले ही हिंदी को अंगीकृत कर लिया था, लेकिन गाधी–नेहरू की कांग्रेस और सोनिया–राहुल की कांग्रेस में जमीन–आसमान जैसे अंतर हैं। कांग्रेसी संरक्षण ने ही हिंदी के मुंह पर नया तमाचा जड़ने का उत्साह बढ़ाया है।

राष्ट्र से अलग किसी भी प्रकार की अस्मिता, पहचान को दंडित करने के लिए नया कानून चाहिए। भारतीय भूभाग में निर्बाध विचरण, जीविका और व्यापार में बाधा डालने वाले अपराध को राष्ट्रद्रोह की परिधि में लेना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा सहित राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने वालों को कड़ी सजा के दायरे में लाना ही होगा।

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, भाषा की अपनी संस्कृति होती है। राष्ट्रभाव मातृभाषा में ही प्रकट होते हैं। संस्कृत ने भारतीय संस्कृति को राष्ट्रव्यापी, वैज्ञानिक और दार्शनिक बनाया था। हिंदी संस्कृत का नया रूप है। हिंदी भारत की सभी आकांक्षाओं को प्रकट करती है। यह राष्ट्र हिंदी में सोचता है, हिंदी में बोलता है, हिंदी में सुनता है और हिंदी में ही गुनता है। गाधी जी हिंदी के जानकार नहीं थे, लेकिन गाधी हिंदी की योजक क्षमता से परिचित थे। उन्होंने 'हिंद स्वराज' में लिखा–हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही होनी चाहिए। गाधीजी ने कहा कि वायसराय से भी हिंदी में ही बोलना चाहिए। स्वाधीनता का महासंग्राम हिंदी में ही लड़ा गया था। मुंबई में दुनिया का नंबर दो फिल्म उद्योग है। यह 60–65 हजार करोड़ से बड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। मुंबई विधानसभा में हिंदी पर गुंडागर्दी है, लेकिन नाना पाटेकर जैसे अनेक प्रतिभाशाली मराठी नायकों की हिंदी फिल्मों और संवाद का सारे देश में स्वागत है। हिंदी राजाश्रय से नहीं बढ़ी। भारत के नए महाराजाओं ने तो 14 सितंबर 1949 के दिन ही अंग्रेजी को महारानी और हिंदी को नौकरानी बना दिया था, लेकिन हिंदी पंख फैलाकर उड़ी। हिंदी व्यापार की भाषा है, सूचना और संचार की भाषा है, राजनीतिक प्रचार की भाषा है, सिर्फ वोट राजनीति के लिए ही वह दुत्कार और तिरस्कार की भाषा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक विधायक को ही नहीं पीटा, उन्होंने महाराष्ट्र निवासियों को भी अपमानित किया है। संविधान सभा ने हिंदी के विकास के लिए संस्कृत से शब्द लेने के नीति निर्देश बताए थे, लेकिन हिंदी वात्सल्य रस से पूरित मां जैसी है। हिंदी ने मराठी गुजराती, तमिल, तेलगू, पंजाबी और राजस्थानी आदि सभी भाषाओं के शब्द अपनाए हैं। उर्दू पहले से ही हिंदी के आंचल में है, विदेशी अंग्रेजी भी पूरी ढिठाई के साथ हिंदी के अंतः क्षेत्र में 'हिंगलिश' होकर घुस गई है। हिंदी सर्वसमावेशी है। हिंदी ज्ञान की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, संस्कृति और दर्शन की भाषा है और इस सबसे ज्यादा वह भारत के मन की भाषा है। वह द्वंद्व–प्रतिद्वंद्व और द्वैत से अद्वैत के संवाद की परत खोलती है। राष्ट्र हिंदी में खिलता है, पलता है, हंसता है और गुंडाराज के थप्पड़ खाकर हिंदी में ही रोता भी है। ताजा विवाद हिंदी भाषा का ही नहीं है। वह भारत की गटर राजनीति की सड़ांध का विकास है। यह एक राष्ट्र के भीतर

शेष पृष्ठ 25 पर...

मूल्यों की दोषपूर्ण नीति

& Mk- Hkjr >|u>|uokyk

I रकार ने गन्ने के मूल्य में कटौती की है। पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य से बढ़ाकर राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाता था। गत वर्ष केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य 108 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि राज्यों ने 160 से 180 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया था। राज्य सरकारें केंद्र के मूल्य से अधिक समर्थन मूल्य घोषित करती थीं, जो किसानों को मिलता था। केंद्र सरकार ने अब राज्यों द्वारा घोषित मूल्य के निर्धारण को समाप्त कर दिया है। केंद्र ने व्यवस्था दी है कि यदि राज्य सरकार ऊंचे मूल्य घोषित करती है तो अंतर को राज्य सरकार को स्वयं वहन करना होगा। चीनी मिलों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य ही अदा करना होगा। राज्य सरकारों की क्षमता नहीं है कि इस भार को वहन कर सकें, इसलिए किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने गत वर्ष के 108 रुपये के मुकाबले इस वर्ष 130 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किया है, जो कि वृद्धि अंकित करता है, परंतु यह वृद्धि भ्रामक है। किसान को 160–180 रुपये के स्थान पर 130 रुपये का घोषित मूल्य ही मिलेगा। केंद्र सरकार की मंशा है कि गन्ने के मूल्य में कटौती हो और तदनुसार आने वाले समय में चीनी के मूल्य में भी गिरावट आए।

केंद्रीय सत्ता की यह नीति केवल चीनी तक सीमित नहीं है। दूसरी फसलों के दाम कम से कम रखने के प्रयास जारी हैं। जैसे गेहूं के मूल्य में पूर्व में प्रत्येक वर्ष में 60–100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की जाती थी। इस वर्ष मात्र 20 रुपये की वृद्धि की गई है। मूल्य को 1080 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जबकि मजदूरी, खाद, डीजल के दाम में निरंतर वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट लाने के चार कारण दिखते हैं। पहला कारण वैश्विक उत्पादन में वृद्धि है। खबरों में कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि इस वर्ष विश्व में गेहूं के अधिक उत्पादन के पूर्वानुमानों को देखते हुए सरकार ने मूल्य न्यून रखे हैं। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि चीनी मिलों को कच्ची चीनी के आयात की छूट मिलनी चाहिए। सरकार चाहती है कि घटते वैश्विक मूल्यों का लाभ हमारे उपभोक्ताओं को मिले।

प्रतीत होता है कि सरकार पर विकसित देशों का दबाव है कि भारत की खाद्य सुरक्षा नष्ट करके हमारे देश को दूसरे देशों पर परावलंबित बना दिया जाए। अपनी खाद्य सुरक्षा को विश्व बाजार को सौंप कर देश की संप्रभुता को नष्ट नहीं करना चाहिए। मुगल बादशाहों ने भारतीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को ब्रिटिश राज्य को सौंप कर देश की गुलामी को न्यौता दिया था।

बाजार मूल्यों में वृद्धि के बावजूद शुद्ध मूल्य में गिरावट आ सकती है। जैसे गेहूं का बाजार मूल्य गत वर्ष 1080 रुपये के मुकाबले इस वर्ष 1100 रुपये हो गया है, परंतु इसी अवधि में महंगाई बढ़ने से रुपये की क्रय शक्ति घट गई। पिछले वर्ष 1080 रुपये में 22 किलोग्राम दाल मिलती थी। इस वर्ष 1100 रुपये में 11 किलो दाल मिलेगी। अतः बाजार मूल्य में वृद्धि के बावजूद शुद्ध मूल्य में गिरावट आ रही है। यह गिरावट बताती है कि दूसरे देशों में उत्पादन की कुशलता में सुधार हुआ है, जैसे किसान रहट के स्थान पर ट्यूबवेल से सिंचाई करे तो लागत कम हो जाती है। इसी प्रकार के तमाम सुधारों से वैश्विक मूल्यों में गिरावट आई है। सरकार चाहती है कि भारतीय किसान भी इन कुशल तकनीकों का प्रयोग करें, अपनी लागत में कटौती करें और सस्ते माल का उत्पादन करें। इसलिए सरकार गन्ने एवं गेहूं के मूल्यों में कटौती करने को उद्यत है।

पिछले वर्ष से व्याप्त हुई वैश्विक मंदी ने भी मूल्यों में गिरावट लाने का कार्य किया है। 2005 से 2008 के वर्षों में विश्व बाजार में तेजी थी और देश में मानसून भी सामान्य था। इससे किसानों को ऊंचे मूल्य और ऊंचे उत्पादन का दोहरा लाभ मिला था। यह परिस्थिति असामान्य थी, जैसे लाटरी निकल जाती है। इस विशेष परिस्थिति को लंबे समय तक जारी नहीं रखा जा सकता है। अतः सरकार चाहती है कि पूर्व की तेजी की चाल को छोड़कर किसान पुनः सामान्य चाल पर वापस आएं। तीसरा कारण सरकार के पास पर्याप्त बफर स्टाक का उपलब्ध होना है। मसलन सरकार के पास गेहूं का 284 लाख टन का भंडार उपलब्ध है, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से 110 लाख टन ही पर्याप्त है। बफर स्टाक उपलब्ध होने से सरकार को कृषि उत्पादन में गिरावट का भय नहीं रह गया है। चौथा कारण सरकार की शहरी मध्यम वर्ग को पोषित करने की मानसिकता है। हाल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 40 प्रतिशत की वेतनवृद्धि प्रदान की गई है। इन कर्मियों की माग है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य न्यून रखे जाएं। इसलिए खाद्य पदार्थों के मूल्य में कटौती के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात का योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अनुमोदन किया है। कहा है कि खाद्य पदार्थों के

बढ़ते मूल्य चिंता का विषय नहीं है। इस मुद्दे को हवा दी गई है, क्योंकि देश की सभी नीतियां मध्यम वर्ग के इर्दगिर्द मंडराती हैं और समाज के दूसरे वर्गों की अनदेखी करती हैं। उपरोक्त चार कारणों से सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्य में कटौती करने का निर्णय लिया है।

प्रश्न देश की खाद्य सुरक्षा का है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में देश की जनता का पेट भरने के लिए सरकार को दीर्घकालीन नीति बनानी चाहिए। वर्तमान में जो गेहूं का बफर भंडार है वह एक वर्ष में ही समाप्त हो सकता है। तापमान में वैश्विक वृद्धि के कारण विश्व का पर्यावरण बदल रहा है और जिस प्रकार पिछली खरीफ की फसल नष्ट हुई है उसी प्रकार आने वाली फसल नष्ट हो सकती है। किसान यदि एक बार विरक्त हो गया और उसने नहर की मरम्मत, कुएं की सफाई एवं खेत में गोबर डालने से हाथ खींच लिया तो प्रभाव कई वर्षों तक पड़ेगा। जिस प्रकार लाटरी खुलने पर बुद्धिमान व्यक्ति धंधा करना नहीं छोड़ता उसी प्रकार बफर स्टाक के भरोसे सरकार को कृषि की हत्या नहीं करनी चाहिए। न्यून वैश्विक मूल्यों पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस समय भारत जैसा विशाल देश खाद्य पदार्थों का आयातक बन जाएगा उस समय वैश्विक मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो सकती है।

जनहित की दृष्टि से भी खाद्य पदार्थों का मूल्य न्यून बनाए रखना उचित नहीं लगता। देश की 60 प्रतिशत जनता कृषि से जीविकोपार्जन करती है। कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि का एक हिस्सा खेत मजदूर को भी मिलता है। शहरी गरीब के लिए ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि खेत मजदूर की आय में वृद्धि होती है तो शहरी गरीब पुनः गांव को पलायन कर सकता है। खाद्य पदार्थों के मूल्य न्यून रखने का लाभ मुख्यतः शहरी मध्यम वर्गीय लोगों को होता है। इन 20 प्रतिशत लोगों के स्वार्थ की सिद्धि के लिए 80 प्रतिशत जनता को त्रास नहीं देना चाहिए।

वैश्विक कुशलता की दृष्टि से कृषि उत्पादों के मूल्य में कटौती की जा सकती है, परंतु वैश्विक कुशलता का अंतिम लक्ष्य जनहित ही है। ऐसी कुशलता किस काम की जो जनता के त्रास का कारण बने। प्रतीत होता है कि सरकार पर विकसित देशों का दबाव है कि भारत की खाद्य सुरक्षा नष्ट करके हमारे देश को दूसरे देशों पर परावलंबित बना दिया जाए। अपनी खाद्य सुरक्षा को विश्व बाजार को सौंप कर देश की संप्रभुता को नष्ट नहीं करना चाहिए। मुगल बादशाहों ने भारतीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा को ब्रिटिश राज्य को सौंप कर देश की गुलामी को न्यौता दिया था। ■

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)

पृष्ठ 6 का शेष

House, but that is a different matter. I have not taken recourse to the Privilege Motion, but I have sought from the Government immediate placing of this Report on the Table of the House. Personally, I am proud of my association with the Ayodhya Movement. I was distressed by the demolition of that structure, but so far as the Movement is concerned, मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में मेरा अयोध्या मूवमैंट के साथ जुड़ना और वहां पर जनता की इच्छा के अनुसार उस स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बने, यह मेरे जीवन की साध है और जब तक यह साध पूरी नहीं होगी, मैं इसके लिए कार्य करता रहूंगा। आज वहां पर एक मंदिर बना हुआ है और कुछ नहीं है, मंदिर ही है। लेकिन वह मंदिर जिस रूप में है, वह कोई भगवान रामचन्द्र के जन्म स्थान के अनुरूप नहीं है। मैं चाहूंगा कि वैसा ही एक भव्य मंदिर बने। यह मेरे मन की इच्छा है।

आज गृह मंत्री जी से मेरी मांग है कि वह बिना अधिक विलंब के इस रिपोर्ट को सदन के सामने रखें जिससे हमें समझ में आए कि लिब्रहान कमीशन ने क्या कहा है। मेरी कम से कम उनके सामने जितनी एवीडेंस की रिपोर्ट हो गई, निश्चित रूप से दस दिन तक मैंने लिब्रहान कमीशन के सामने अपना बयान दिया, अपना विचार रखा, अयोध्या मूवमैंट के बारे में कहा।

डिमॉलिशन मैं कभी एक्सपैक्ट नहीं करता था, डिमॉलिशन जिस प्रकार हुआ, मैं आपको कह सकता हूं कि वहां पर जितने लोग थे, वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थे, विश्व हिन्दू परिषद के थे, बीजेपी के थे। सबने पूरी कोशिश की कि जितने लोग उसे तोड़ रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, वे ऐसा न करें। विश्व हिन्दू परिषद् के सबसे बड़े नेता श्री अशोक सिंघल को उन लोगों द्वारा मैन हैंडल किया गया। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। ■

पृष्ठ 23 का शेष

द्विराष्ट्रवाद चलाने का नया जिन्नावाद है। यह भारत के एक भूभाग को राष्ट्र से भिन्न महाराष्ट्र सिद्ध करने का वोटलोलुप गंदा धंधा है। यह देश को तोड़ने का नग्न और निंदनीय प्रयास है। यह भारत के सड़े हुए राजनीतिक दल तंत्र का बदबूदार प्रसंग है।

इस सड़ांध का क्षेत्र मुंबई से दिल्ली तक पसरा हुआ है। राज्य सरकार ने गुंडाराज को संरक्षण दिया और केंद्र भी मौन रहा। बुनियादी प्रश्न यह है कि कांग्रेसनीत केंद्र व राज्य सरकार के इस महापाप के विरुद्ध अन्य दलों के माननीय सासदों ने संसद में कोई कारगर हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? क्या निलंबन पर्याप्त है? यह मसला सभी दलों के लिए राष्ट्रीय अखंडता का प्रश्न क्यों नहीं है? अब भारत को एक नए अधिनियम की आवश्यकता है। राष्ट्र से अलग किसी भी प्रकार की अस्मिता, पहचान को दंडित करने के लिए नया कानून चाहिए। भारतीय भूभाग में निर्बाध विचरण, जीविका और व्यापार में बाधा डालने वाले अपराध को राष्ट्रद्रोह की परिधि में लेना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा सहित राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने वालों को कड़ी सजा के दायरे में लाना ही होगा। ■

(लेखक उप्र सरकार के पूर्व मंत्री हैं)

गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन

ग न्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर 19 नवम्बर को नई दिल्ली में किसानों ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया। उधर, विपक्षी दलों ने लोकसभा में जमकर विरोध किया। विपक्ष के दबाव और दिल्ली की सड़कों पर किसानों के तेवरों के चलते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से इस मुद्दे पर चर्चा की। खबरों के अनुसार केन्द्र सरकार गन्ना अध्यादेश पर विचार करने को तैयार हो गई है। इस बीच, कुछ विपक्षी दलों ने कहा है कि यदि सरकार ने गन्ने के लिए, तय कीमतों को वापस नहीं लिया तो संसद नहीं चलने दी जाएगी।

किसानों का जोरदार प्रदर्शन

रामलीला मैदान से हाथों में गन्ना लिए और सरकार विरोधी नारे लगाते रैली की शक्ल में जंतर–मंतर की ओर हजारों किसानों के जत्थों ने कूच किया। रैली में भाजपा नेता अरूण जेटली, सपा नेता मुलायमसिंह यादव, माकपा नेता बासुदेव आचार्य, रालोद अध्यक्ष अजित सिंह, भाकपा के डी राजा व गुरूदास दास गुप्ता और अमर सिंह शामिल हुए। रैली में जद यू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि अध्यादेश वापसी तक आन्दोलन जारी रहेगा व संसद नहीं चलने देंगे।

लोकसभा में हंगामा

लोकसभा में हंगामे के चलते एक बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों ने चर्चा को लेकर दबाव बनाया, राजग के साथ सपा और वामपंथी दलों ने भी साथ दिया। राजग इस मुद्दे पर 20 नवम्बर को लोकसभा में कार्यस्थगन व राज्यसभा में प्रश्नकाल स्थगन का प्रस्ताव लाने जा रहा है। लोकसभा में विपक्ष की उपनेता सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान निकालने का सुझाव दिया।

पीएम ने की आपात बैठक

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गृहमंत्री पी. चिदम्बरम, वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी, कानून मंत्री वीरप्पा मोइली और कृषि मंत्री शरद पवार के साथ बैठक की, जिसमें समर्थन मूल्य पर फिर विचार किए जाने की खबर है। ■

गन्ना किसानों की मांगें जायज : राजनाथ सिंह

गन्ना किसानों का आंदोलन व उनकी मांगे जायज हैं, भारतीय जनता पार्टी किसानों और उन संगठनों के साथ है जो आंदोलन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसानों की मांग पूरी होने तक संसद नहीं चलने देगी।

यह बातें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गाजियाबाद से सांसद श्री राजनाथ सिंह ने जलालाबाद में आयोजित चौपाल के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने गन्ना किसानों के साथ घिनौना मजाक किया है। और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। यदि वह चाहे तो किसानों को गन्ने का मूल्य 280 से तीन रूपये क्विंटल दिला सकती है। लेकिन वह मिल मालिकों का भला चाहती है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उस समय चीनी दस से ग्यारह रूपये हुआ करती थी। उस समय मैंने किसानों को गन्ने का भाव 165 रूपये दिलाया था। आज चीनी चालीस रूपये किलो बिक रही है। ऐसे में किसान को गन्ने का भाव 300 रूपये मिलना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि जब तक गन्ना किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। आगामी 19 नवम्बर से चलने वाले शीतकालीन सत्र में संसद नहीं चलने दी जाएगी। देश व समाज का वही नेता भला कर सकता है जो बिना वोट की चिंता किए कड़े फैसले ले सके। शिक्षा में नकल रोधी अध्यादेश लाकर मैंने उसी दृढ़ता का परिचय दिया था। जब पढ़ाई के समय ही बच्चों को नकल चोरी सिखा दी जाएगी वह आगे चलकर देश को कैसा भविष्य देंगे।

मैंने वह प्रयास समाज सुधार के लिए ही किया था। ग्राम जलालाबाद को जाने वाले मार्ग पर रेलवे लाइन पर फाटक, कन्या डिग्री कॉलेज पर उन्होंने मांगें पूरी कराने का आश्वासन देते हुए कहा मैं प्रयास ही कर सकता हूं पक्का वादा नहीं, क्योंकि प्रदेश में बहन जी बैठी हैं और केन्द्र में भी दूसरी मैडम की ही चल रही है। ऐसे में पक्का वादा किया जाना झूठ बोलने के समान है और मैं झूठ में विश्वास नहीं करता। कार्यक्रम की अध्यक्षता धर्मपाल सिंह ने की। संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष आशू वर्मा ने किया। ■

भारत एक विविधतापूर्ण देश है- यही उसकी राष्ट्रीय संस्कृति है : लालकृष्ण आडवाणी

गत 22 नवम्बर को नई दिल्ली में आयोजित 'आर्क डिओसीज आफ दिल्ली के स्वर्णजयंती समारोह के समापन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा को अल्पसंख्यक अथवा ईसाई–विरोधी पार्टी का भ्रामक प्रचार करने वालों को आड़े हाथों लिया। इस अवसर पर उनके द्वारा दिए गए उद्‌बोधन का हिंदी भावानुवाद नीचे प्रस्तुत है।

रेव. विंसेट एम. कांसेसाओ– दि आर्क बिशप आफ दिल्ली, रेव. फ्रांको मुलक्कल आक्जिलियरी बिशप आफ दिल्ली, अन्य आदरणीय प्रीस्ट्स, प्रिय बहनों और भाईयों,

मेरे लिए यह हर्ष और सम्मान का विषय है कि मुझे ''आर्कडिओसीज आफ दिल्ली के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन अवसर पर आमंत्रित किया गया, जिसकी स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। मैं इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

भारतीय संस्कार: मजहब की स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक एकता

मित्रों, भारत विविधताओं का देश है। हम यहां अनेक बातों में धर्म, भाषा, रीति–रिवाज, वेश–भूषा की विविधता के स्वरूप का दर्शन करते हैं। भारत ने इन विविधताओं को किसी परिस्थितिवश बाध्यताओं के रूप में नहीं अपनाया है, बल्कि इसके पीछे भारत की जन्मजात समाहित प्रकृति का हाथ रहा है।

भारत की सभ्यता युगों पुरानी है और हमने सदैव इन विविधताओं का सम्मान करना और स्वीकारने की अद्‌भुत विशेषताओं का परिचय देते हुए इन्हें अपने में समाहित किया है और इस एकता का हिस्सा बनाया है। यही समाहित शक्ति हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतीक है। यही हमारे देश के आवश्यक संस्कार रहे हैं।

हमें अपनी विविधता पर नाज होना चाहिए किन्तु, साथ ही हमारे समाज के सभी विविध वर्गों का भी अनिवार्य कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे भारत की इस अनिवार्य एकता की शक्ति को निरंतर कायम रखें।

मैं स्वयं भी चर्च संचालित स्कूल– सेंट पेट्रिक हाई स्कूल, कराची का विद्यार्थी रहा हूं, जो विभाजन से पूर्व अविभाजित भारत का भाग था। स्कूल में हमारे सभी अध्यापक, जिसमें प्रिंसिपल मोडेस्टीन शामिल थे, क्रिश्चियन थे। मैं सदा ही अपने अध्यापकों का आभारी रहा हूं। धर्म के विषय में भारत कभी भी ऐसा देश नहीं रहा, जिसने अन्य धर्मों का त्याग किया हो और कभी भी धर्मनिष्ठ और आध्यात्मिक लोगों के लिए अपने द्वार बंद नहीं किए। 'सर्व पंथ समादर' में हमारा विश्वास भारत की युगों पुरानी सेक्युलरिज्म पर चलने का आधार है।

''एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्तिः'' ही हमारे लोगों की सोच रही है, जो वैदिक युग से चली आ रही है। इसीलिए जब–जब भी हमारे देश में दूर–दूर से प्रज्ञावान और साधु व्यक्तियों ने यहां आ कर 'सत्य' की नई व्याख्या की तो हमने सदैव उनका स्वागत किया है। इनमें से एक प्रज्ञावान और सम्मानीय व्यक्ति था– सेंट थामस, जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक था और जो 52 एडी में मालाबार तट पर ईसोपदेश लेकर यहां पहुंचा था। भारत में पहला ईसाई चर्च पालायुर में है और इसे सेंट थामस चर्च के नाम से जाना जाता है।

क्या ईसामसीह भारत आए थे?

निःसंदेह यह एक सोच है– और इस सोच के बारे में बहुत कौतुहल भी छुपा है कि ईसा मसीह स्वयं भारत आए थे, जब वे युवा थे।

मैंने अभी हाल में 'टाइम्स आफ इण्डिया' में पढ़ा था कि ब्रिटिश प्रोड्‌युसर केंट वाल्विन ईसा मसीह के भारत से सम्बंध पर खोज करना चाहते हैं। उनकी एक फिल्म 'यंग जीसस– दि मिस्सिंग्स ईयर्स' नाम से बनाने की योजना है और समझा जाता है कि इसमें क्राइस्ट के जीवन के उन वर्षों का जिक्र होगा, जिनका वर्णन 'गोस्पल' में नहीं मिलता है और जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यह वर्ष भारत में बिताए थे। ऐतिहासिक तथ्य चाहे जो भी हो, सच यही है कि जिस देश में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उनके उपदेश उसी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, बल्कि उनका सम्बंध पूरे विश्व से है।

भारत सभी धर्मों का आदर करता है

मित्रों, यह कोई राजनैतिक मंच नहीं है। अतः, मैं किसी राजनैतिक विषय पर नहीं बोलूंगा। फिर भी, यह एक ऐसा अवसर है, जिसके बारे में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। यह लगातार प्रचार किया जाता है कि मेरी पार्टी भाजपा अल्पसंख्यक विरोधी है और क्रिश्चियन–विरोधी है। मैं जरा इतिहास की तरफ मुड़ना चाहूंगा और कुछ उदाहरण पेश कर इस सोद्देश्य प्रचार को समाप्त करना चाहूंगा।

आपमें से बहुत से लोग जानते होंगे कि भाजपा से पूर्व भारतीय जनसंघ था, जिसकी स्थापना डा. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने की थी। डॉ. मुकर्जी विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने पं. नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योगमंत्री के रूप में कार्य किया था।

प्रचास के दशक के पूर्वार्ध में देश के विभिन्न भागों में पार्टी का गठन करते हुए उन्होंने बैरिस्टर बी.के. जॉन को मद्रास प्रांत में जनसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया था, जो संयोगतः कलकत्ता में डा. मुकर्जी के सहपाठी थे।

यही प्रचार उस समय भी सुना गया

था। बैरिस्टर जॉन से पूछा गया था: ''एक क्रिश्चियन होते हुए आपने एक साम्प्रदायिक पार्टी का पदभार कैसे स्वीकार कर लिया?'' उनका उत्तर था: ''मैं डा. एसपी मुकर्जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वह कभी भी किसी साम्प्रदायिक पार्टी के प्रजीडेण्ट नहीं हो सकते।''

मैं अपने राजनैतिक जीवन से भी एक उदाहरण देना चाहूंगा।

अपनी स्कूली पृष्ठभूमि के कारण मैं प्रायः अपने राजनैतिक संदेशों में भी क्रिश्चियन रूपकों का प्रयोग किया करता हूं। जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो उस दिन 'ईस्टर संडे' था, जिसे जीसस क्राइस्ट का पुनर्जीवन माना जाता है। आपमें से जो लोग भाजपा निर्माण के इतिहास से परिचित होंगे, वह जानते होंगे कि इससे पूर्व हम जनता पार्टी में थे।

जनता पार्टी का जन्म सभी आपातकालीन–विरोधी पार्टियों को आपस में मिला कर किया गया था, जिसमें जनसंघ भी शामिल था और इसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को चुनौती देने के लिए इस संगठन की स्थापना हुई थी। किन्तु बाद में हमें अपनी अलग पार्टी बनाने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि हममें से वह लोग जो पूर्ववर्ती जनसंघ से सम्बंध रखते थे, 1979 में संदिग्ध ''दोहरी सदस्यता'' के मुद्दे पर जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। जनता पार्टी में हमारे कुछ सहयोगियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ सम्बंध रखने पर आपत्ति की थी। यह निष्कासन भी गुड फ्राइडे को हुआ, जो जीसस क्राइस्ट का 'क्रूसीफिकेशन दिवस' था।

अतः मैंने भाजपा के स्थापना सम्मेलन के अवसर पर अपने भाषण में कहा था: ''यह बात कहीं अधिक महत्व रखती है कि हमें क्राइस्ट के 'क्रूसीफिकेशन' के दिन जनता पार्टी से निष्कासित किया गया और यह भी कि हमने क्राइस्ट के पुनर्जीवन के दिन भाजपा के रूप में फिर से हमारा राजनैतिक जन्म हुआ।''

मैं जीसस क्राइस्ट के सार्वभौमिक शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेश का बड़ा सम्मान करता हूं। मैं स्वातंत्र्योत्तर युग में भाजपा के स्वतंत्रता संघर्ष और भारत के राष्ट्र–निर्माण दोनों में ही अपने ईसाई बंधुओं के योगदान की गहन कद्र करता हूं। ■

जन-विरोधी बसपा सरकार के खिलाफ भाजपा ने जारी की चार्जशीट

Hkk जपा ने 19 नवम्बर को बसपा सरकार के खिलाफ लखनऊ में 'चार्जशीट' जारी कर दी। इसमें सरकार पर गंभीर आरोप लगाये गए हैं। पार्टी ने 'चार्जशीट' की प्रति राज्यपाल को भी सौंपी,जिनसे बसपा सरकार को भ्रष्ट, जन–विरोधी, संविधान–विरोधी और तानाशाह बताते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजने का अनुरोध किया गया।

हुकुम सिंह, सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्रदेव सिंह, सुरेश श्रीवास्तव और जयप्रकाश चतुर्वेदी शामिल थे।

बाद में प्रेस कान्फ्रेन्स में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नजर में बसपा सरकार 'मुख्य अभियुक्त' है, जबकि पुलिस एवं प्रशासन 'सह अभियुक्त'? 'चार्जशीट' में बसपा सरकार पर दस मुख्य आरोप लगाये गए हैं, जिनमें संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, माफिया अराजक तत्वों को शह, दलित एक्ट के दुरुपयोग, राजकोष की लूट, आम जनता से रंगदारी वसूली, निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे, मानवाधिकार उल्लंघन एवं पुलिस अत्याचार, आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी, किसान उत्पीड़न तथा व्यापारी अपहरण एवं उत्पीड़न शामिल हैं।

लखनऊ में राज्यपाल बी.एल. जोशी को ज्ञापन सौंपते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. रमापति राम त्रिपाठी व अन्य पार्टी नेता

प्रदेश अध्यक्ष डा.रमापति राम त्रिपाठी के नेतृत्व में वरिष्ठ पार्टी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल बीएल जोशी से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन और 'चार्जशीट' सौंपी। ज्ञापन में कहा गया कि बसपा सरकार असंवैधानिक हो चुकी है।

इसके शासन में अपराध, भ्रष्टाचार, तानाशाही, उत्पीड़न और बेरोजगारी चरम पर हैं। पुलिस 'उत्पीड़क एजेन्सी' है। विरोध करने के मौलिक अधिकार पर लाठी मिलती है। सरकार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान एवं उपेक्षा कर रही है। ऐसी सरकार ने राज्य में शासन करने का संवैधानिक, राजनैतिक व नैतिक अधिकार खो दिया है। प्रतिनिधिमंडल में विधानमंडल दल के नेता ओम प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित,

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ने राज्यपाल से केन्द्र को इस सरकार के खिलाफ आख्या भेजने का अनुरोध किया है। यह मांग पूरी न होने पर भाजपा कार्यकर्ता 'चार्जशीट' लेकर गांव–गांव जायेंगे, और विभिन्न स्तरों पर जन पंचायतें आयोजित करके सरकार के खिलाफ अभियान चलायेंगे।

भाजपा की इस 'चार्जशीट' को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाकर पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर वितरण की योजना है। ■

भारतीय संविधान के ६० वर्ष : 'संविधान सम्मान समारोह'

अनुसूचित जाति के आरक्षण पर कुठाराघात

Xत 26 नवम्बर, 1949 को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'भारतीय संविधान' को अंतिम रूप प्रदान करते हुए संविधान सभा में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया और उसी दिन संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। यहीं संविधान 26 जनवरी, 1950 को भारत में लागू हुआ और भारतीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से चिंतन करते हुए भारत को गौरवशाली राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक– आर्थिक– राजनैतिक न्याय दिलाने तथा समता, बंधुता और स्वतंत्रता को संविधान में समाहित किया था। ऐसे विश्व प्रसिद्ध भारतीय संविधान के 60 वर्ष पूरे होने के गौरवमयी स्मृति में 'अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ मंच' द्वारा आगामी 26 नवम्बर, 2009 से 26 जनवरी 2010 तक 'संविधान सम्मान समारोह' का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

'अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ मंच एक गैर राजनैतिक सामाजिक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्राप्त आरक्षण और उनके अधिकारों को बचाना है। '26 नवम्बर 2009' को देश की प्रादेशिक राजधानियों एवं प्रमुख नगरों में मंच की ओर से 'संविधान सम्मान समारोह' मनाया जाएगा। 26 नवम्बर, 2009 से 26 जनवरी 2010 तक चलने वाले इस गौरवशाली श्रृंखला में अनुसूचित जाति के लिए भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा इन अधिकारों के कार्यान्वयन में बरती गई कोताही, उनके अधिकारों के प्रति जनजागरण जैसे कार्यक्रमों को जिला स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने और भारतीय संविधान में उल्लिखित हमारे अधिकारों के संरक्षण संबंधी गौरवशाली मूल भावनाओं, नागरिकों के कर्त्तव्यों, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के दायित्वों को जन–जन तक पहुंचाने के लिए देश के प्रमुख नगरों में स्थित स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर गोष्ठियां, प्रदर्शन, धरना एवं जनजागरण यात्राओं का आयोजन मंच के नेतृत्व में होंगे। मंच की ओर से इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु सरकारी कर्मचारियों के संगठनों, सामाजिक व दलित संस्थाओं, साहित्यकारों, पत्रकारों और प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है।

26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकृत व अंगीकृत किया गया था। इस गौरवपूर्ण अवसर पर गत 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में आतंकवादियों ने हमला करते हुए हमारे संविधान व प्रजातांत्रिक पद्धति पर भी एक प्रकार से हमला किया था। हम इस अवसर पर इसकी घोर निंदा करते हुए इस हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहेंगे। हम देश के महापुरूषों के गौरवशाली व्यक्तित्व तथा कृतित्व के बारे में इस देश के बच्चों और युवापीढ़ी को अवगत कराएं ताकि वे राष्ट्र की एकता भारतीय कला–संस्कृति, साहित्य, भाईचारा और गौरवशाली विकास में अपना बहुमूल्य योगदान करते हुए सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए भारत को दुनिया में गौरवशाली पहचान दिला सकें।

हिन्दू धर्म की सामाजिक व्यवस्था के चलते पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए वर्ष 1932 में हुए 'पूना पैक्ट' के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सर्वाधिक समय तक केन्द्र एवं प्रदेश में रहीं कांग्रेसी सरकारों ने इसे ईमानदारी के साथ लागू नहीं किया। वोट की राजनीति के चलते उन्हें शोषण से मुक्ति के लिए कोई सकारात्मक और सृजनात्मक प्रभावकारी नीतिगत योजनाओं को न तो बनाया गया और न ही उनके लिए बनाई योजनाओं को भलीभांति लागू किया गया।

केन्द्र की यूपीए सरकार ने वर्ष 2004 में मुस्लिम समाज की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन करने के लिए पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर के नेतृत्व में सच्चर कमेटी का गठन था। इस रिपोर्ट में मुस्लिम समाज को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता देने उल्लेख किया गया। केन्द्र सरकार ने इस कमेटी के आधार पर देश के आर्थिक संसाधनों पर पहला अधिकार अनुसूचित वर्ग की बजाए मुस्लिम समुदाय को देते हुए विशेष प्रावधान किए। इतना ही हीं कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम को अपने पाले में खींचने के लिए जस्टिस रंगनाथ मिश्र कमीशन की नियुक्ति की। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में धर्मांतरित दलित ईसाई और मुस्लिम को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देने हेतु अपनी संस्तुति की। यदि उक्त संस्तुति को केन्द्र सरकार लागू करती है तो अनुसूचित जाति को संविधान के अनुसार मिलने वाले 15 प्रतिशत राजनैतिक एवं सेवा क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएगा।

वर्ष 1936 में पहली बार धर्मांतरित दलित ईसाई और मुस्लिम को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग उठाई गई थी। तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने इस मांग को अस्वीकार करते हुए कहा था कि ''किसी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा।'' परिणामस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत द्वारा ये मांग सदा–सदा के लिए समाप्त कर दी गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र दिनांक 27 जून, 1961 के माध्यम से मजहब के आधार पर आरक्षण की मांग का विरोध किया था। तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री

हनुमनथप्पा ने धर्मांतरित दलित ईसाई और मुस्लिम को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने का प्रबल विरोध किया था। ऐसा ही विरोध तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अन्य अध्यक्षों ने किया।

संविधान सभा की बैठकों के दौरान भी ईसाई और मुस्लिम समाज के लिए मजहब के आधार पर आरक्षण की मांग भी उठाई गई थी लेकिन इसे न केवल डॉ. अम्बेडकर ने बल्कि पं. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सी. राजगोपालाचारी तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मजहब के आधार पर ईसाई और मुस्लिम को आरक्षण देना स्वीकार नहीं किया था। उक्त सभी नेताओं का मानना था कि हिन्दू मजहब को मानने वाले सदियों से शोषित और अस्पृश्यता से पीड़ित लोगों को ही अनुसूचित जाति की श्रेणी में रख कर उन्हें आरक्षण का लाभ देना न्यायसंगत होगा; क्योंकि ईसाइयत और इस्लाम मजहब को मानने वाले कभी भी अस्पृश्यता से पीड़ित नहीं हुए और न ही उन्होंने कभी सामाजिक विषमताओं को झेला है। वैसे भी ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग अपने–अपने धर्म में जातिवाद और छुआछूत को नहीं मानने का दावा करते हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति की देश में आबादी बढ़कर 18 प्रतिशत से ज्यादा है, उनके आरक्षण को प्रतिशत बढ़ाने की बजाए उनके लिए निर्धारित 15 प्रतिशत आरक्षण में दलित ईसाई और मुस्लिम को शामिल कर उन्हें एक प्रकार से मिलने वाले अधिकारों से कांग्रेस के नेतृत्व में बनी यूपीए सरकार वंचित करने का काम ही कर रही है। यूपीए सरकार की वोट बैंक पर आधारित धर्मांतरितों को आरक्षण देने के प्रयासों का मंच द्वारा विगत 2 वर्षों से विरोध किया जाता रहा है। इस संबंध में मंच का प्रतिनिधि मंडल वर्ष 2008 में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से मिलकर उन्हें पूर्व एवं वर्तमान परिस्थितियों से अवगत करा चुका है।

अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान को आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को पारित करते हुए उसे केन्द्र सरकार के पास एक षड्यंत्र के पास भेजा। हमें आशंका है कि कांग्रेस अपने प्रभाव वाले राज्यों की विधानसभाओं से इसी प्रकार का प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास करेगी जिसे भविष्य में धर्मांतरितों को आरक्षण देने का आधार बनाया जा सकेगा। कांग्रेस के इस अनुसूचित जाति विरोधी षड्यंत्र की हम घोर निंदा करते हैं। यदि ऐसा होता है तो यह अनुसूचित जाति के लिए प्रकार से कुठाराघात होगा। ग्रामीण अंचलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ईसाई मिशनरियों से निकलने वाले बच्चों से कैसे मुकाबला करते हुए आरक्षण का लाभ ले सकेंगे? इससे आरक्षण का ही मूलमंत्र बेमानी हो जाएगा।■

निशंक ने औद्योगिक पैकेज की मियाद बढ़ाने की मांग की

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने राज्य के लिए औद्योगिक पैकेज की अवधि वर्ष 2020 तक बढ़ाने की केन्द्र सरकार से मांग की है। इस वक्त उत्तराखंड की औद्योगिक पैकेज मार्च 2010 तक दिया गया है।

निशंक ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जनवरी 2003 में उस वक्त के प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड के लिए मार्च 2013 तक औद्योगिक पैकेज मंजूर किया था, लेकिन वर्तमान यूपीए सरकार ने इसे घटा कर मार्च 2010 तक कर दिया। उन्होंने कहा कि यह विषम परिस्थितियों वाले नवोदित राज्य उत्तराखंड के साथ अन्याय है।

निशंक ने कहा कि अभी तक राज्य को 40 हजार करोड़ रूपऐ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं लेकिन वास्तविक निवेश 16 हजार करोड़ रुपए ही हुआ है। इस तरह औद्योगिक पैकेज की अवधि नहीं बढ़ना राज्य के लिए नुकसानदेह होगा।

निशंक ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर कहा है कि समान प्राकृतिक परिस्थितियों को देखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों की तरह ही उत्तराखंड के लिए भी औद्योगिक पैकेज वर्ष 2020 तक के लिए स्वीकृत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष 14 जनवरी से हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार ने पहले कुंभ मेले के लिए चार सौ करोड़ रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की थी। इसके अलावा 330 करोड़ रूपए की अतिरिक्त सहायता राज्य की अन्य अवस्थापना आवश्यकताओं के लिए प्राप्त होनी थी। पर अब राज्य को मिलेन वाली पूरी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता चार हजार करोड़ रूपए तक ही सीमित कर दी गई है। निशंक ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में अनुरोध किया है कि वार्षिक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की 330 करोड़ रूपए की राशि यथावत रखी जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में देश–विदेश से लगभग छह करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इस मेले से सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड से चीन और नेपाल की सीमाएं लगती हैं, इसे देखते हुए भारत सरकार को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीमावर्ती राज्य होने और खास तौर पर चीन से इसकी सीमा लगने के मद्देनजर घुसपैठ की आशंका को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ओर से केन्द्र से पर्वतीय सुरक्षा बल के गठन की मांग की गई है और केन्द्र को इस मांग के संदर्भ में याद भी दिलाया गया है।

उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के मुद्दे पर पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में निशंक ने कहा कि दीक्षित आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। उस पर चर्चा के बाद सभी दलों की जो राय होगी उसी के अनुरूप काम किया जाएगा।